● वर्ष : 17 ● अंक : 113 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

दैनिक लोकतंत्र की शान

लोकतंत्र का स्तंभ

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दिल्ली से प्रकाशित मंगलवार 10 फरवरी 2026

भारत- सेशेल्स के रिश्ते नए चरण में

हिंद महासागर के साझा भविष्य को देंगे आकार : मोदी

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत और सेशेल्स के संबंध केवल राजनयिक संपर्क तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह रिश्ता सदियों पुराना, गहरा और विश्वास पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत और सेशेल्स सिर्फ भूगोल से ही नहीं, बल्कि इतिहास, भरोसे और भविष्य के लिए एक साझा विज़न से भी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक अर्मिनी के साथ यहां हैदराबाद हाउस में संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत और सेशेल्स का नाता केवल आज का नहीं है, बल्कि यह अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाला संबंध है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर की लहरें सदियों से दोनों देशों के लोगों को जोड़ती आई हैं। इन तटों पर व्यापार फला–फूला, संस्कृतियों का मेल हुआ और आपसी विश्वास की परंपराएं मजबूत होती गईं। एक समुद्री पड़ोसी और भरोसेमंद साझेदार के रूप में सेशेल्स भारत के महासागर विज़न का अभिन्न हिस्सा है और दोनों देशों का सहयोग जल, थल और नभ तक फैला हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चाओं में भारत–सेशेल्स साझेदारी को और अधिक सशक्त बनाने

का मार्ग प्रशस्त हुआ है। दोनों देश अपने आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखने पर सहमत हुए हैं। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने के साथ-साथ वित्तीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल समाधान के क्षेत्र में भी सहयोग को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मोदी ने कहा कि विकास साझेदारी भारत–सेशेल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है और भारत के सभी प्रयास सेशेल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित रहे हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत ने सेशेल्स के लिए 175 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज सामाजिक आवास, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं को समर्थन देगा। इन पहलों से सेशेल्स के लोगों, विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स की क्षमता निर्माण में भारत के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत को सेशेल्स का एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार बताते हुए कहा कि किफायती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति, चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास में दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा और जलवायु के क्षेत्र में सहयोग को सतत विकास की साझा प्रतिबद्धता से प्रेरित बताते हुए उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु-अनुकूल और लचीले समाधानों पर सहयोग को और विस्तार दिया जाएगा।

सेशेल्स के राष्ट्रपति ने राजघाट में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने आज हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सेशेल्स के मैत्रीपूर्ण संबंधों के 50 साल पूरे होने पर द्विपक्षीय सहयोग, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले राष्ट्रपति हर्मिनी राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शांति, अहिंसा और सत्य का गांधीजी का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। राष्ट्रपति हर्मिनी ने इससे पहले आज सुबह विदेशमंत्री डॉ. एस. जयशंकर से भी मुलाकात की। बातचीत में समुद्री पड़ोसी देशों के रूप में क्षेत्रीय आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा के लिए "विजन महासागर" को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। रविवार को उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुंबई में मुलाकात की थी। इस दौरान बंदरगाह आधारित विकास, तटीय प्रबंधन और महाराष्ट्र-सेशेल्स सहयोग के अवसरों पर विस्तृत चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी पांच दिन तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। यह उनकी पदभार ग्रहण करने के बाद पहली भारत यात्रा है और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। इस दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भी मुलाकात करेंगे।

ज्वलंत मुद्दा **संपादकीय**

लोकतंत्र के सर्वोच्च आसन पर उठते सवाल

लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यह वह आसन है, जो सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान एवं जिम्मेदारी का प्रतीक है। संविधान में परिभाषित है। लोकसभा का अध्यक्ष और राज्य सभा का सभापति पार्टीगत राजनीति से ऊपर उठकर सदन का संचालन करेगा। दोनों ही सदन में सभी सदस्यों के हितों के संरक्षण की जिम्मेदारी अध्यक्ष और सभापति की होती है। हालिया घटनाक्रम ने इसी धारणा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी करना कोई साधारण राजनीतिक घटना नहीं है। संसदीय लोकतंत्र की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है। पिछले कई सत्रों से लोकसभा में विपक्ष आरोप लगाता रहा है, उन्हें सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा। बोलने के पहले तरह-तरह से उन्हें रोका जा रहा है।

सदन के अंदर सदस्यों को बोलने की जो स्वतंत्रता थी, उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाधित किया जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जैसे संवैधानिक और परंपरागत अवसर पर भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न मिलना वहीं सत्ता पक्ष के एक सदस्य को बोलने का अवसर दिया गया। इसने असंतोष को आर और पार की लड़ाई में लाकर खड़ा कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष को खुली छूट दी जाती है। जबकि विपक्ष को सवालों ओर नियमों का हवाला देकर बोलने नहीं दिया जाता है। विपक्ष यह कहने से नहीं चूक रहा है, कि आसंदी द्वारा सत्ता पक्ष के लिए अलग, विपक्ष के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष का यह तर्क कि "सदन नियम और परंपरा से चलेगा" अपने आप में सही है, लेकिन सवाल यह है, कि क्या ये नियम सबके लिए समान रूप से लागू हो रहे हैं? पिछले 10 वर्षों में विपक्ष द्वारा जब भी कोई स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष को दिया गया, किसी को मंजूरी नहीं दी गई। जबकि परंपराएं और लोकसभा की कार्यवाही में ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जहां पर विपक्ष को स्थगन प्रस्ताव में बोलने का अवसर दिया गया।

जब सत्ता पक्ष कांग्रेस को "गद्दार" कहता है, तब वह सदन की मर्यादा है? और जब विपक्ष उसका जवाब देना चाहता है, तब उसे "आउट ऑफ प्रोसीडिंग" बताकर रोक दिया जाता है। तो यह किस तरह की निष्पक्षता है? विपक्ष का आरोप है कि अध्यक्ष का व्यवहार निष्पक्ष एवं मध्यस्थता वाला नहीं है। ऐसा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आसंदी का व्यवहार सत्ता पक्ष के रक्षक का है। पिछले वर्षों में जिस तरह से बिल और कानूनों को बिना किसी चर्चा के हो हल्ले में पास कर दिया गया। यही कारण है कि विपक्ष ने अब अविश्वास प्रस्ताव जैसा असाधारण कदम उठाने का मन बनाया है। पिछले 76 सालों में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तीन बार लाया गया है। चौथी बार ऐसी स्थिति बनना अपने आप में असाधारण और चिंताजनक है।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.**9911371802**
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER**786**@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

समीक्षा के दौरान अमित शाह ने भरी हुंकार कहा- अगले माह नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा देश

रायपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति पर एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ-साथ केंद्रीय गृह सचिव, आईबी निदेशक और सीआरपीएफ, एनआईए, बीएसएफ व आईटीबीपी के महानिदेशक भी शामिल हुए। इसके अलावा, नक्सल प्रभावित राज्यों जैसे तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के गृह सचिव व पुलिस महानिदेशक भी मौजूद रहे, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने एक बड़ा लक्ष्य साझा किया और विश्वास जताया कि 31 मार्च 2026 से पहले भारत पूरी तरह से नक्सलवाद के अभिशाप से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार की सुरक्षा-केंद्रित ठोस रणनीति, मजबूत बुनियादी ढांचे का विकास, नक्सलवाद के वित्तीय नेटवर्क पर कड़ा प्रहार और एक प्रभावी आत्मसमर्पण नीति के कारण आज सकारात्मक परिणाम धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि माओवाद के खिलाफ यह लड़ाई बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राज्यों को निर्देश दिया कि वे आपस में ऐसा तालमेल बिठाएं जिससे बचे हुए नक्सली सुरक्षा बलों के दबाव में एक राज्य की सीमा से भागकर दूसरे राज्य में शरण न ले सकें।

मणिपुर में फिर हिंसा, सशस्त्र उग्रवादियों ने कई मकानों में लगाई आग, कर्फ्यू लागू

इंफाल। मणिपुर के उखरुल जिले में एक बार फिर हिंसा का तांडव देखने को मिला। रविवार रात सशस्त्र उग्रवादियों ने लिटान सारेइखोंग क्षेत्र में कई मकानों में आग लगा दी। यह हिंसा तंगखुल नगा समुदाय के एक व्यक्ति पर हुए हमले के बाद उपजे तनाव का परिणाम बताई जा रही है। प्रशासन ने स्थिति को अनियंत्रित होते देख जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट में अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि रविवार शाम को जिले के लिटान गांव में दो आदिवासी समूहों ने पथराव किया, जिसके कारण प्रशासन को निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि देर रात के आसपास लिटान सारेइखोंग में तंगखुल नगा समुदाय के कई मकानों में कुकी उग्रवादियों ने आग लगा दी। पास के ही एक इलाके में कुकी समुदाय के कुछ लोगों के मकानों को भी जला दिया गया। तंगखुल मणिपुर की सबसे बड़ी नगा जनजाति है। लितान सारेइखोंग कुकी बहुल गांव है। रिपोर्ट में एक अधिकारी ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और स्थिति तनावपूर्ण है। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो फुटेज में हथियारबंद लोग गांव में मकानों और वाहनों को आग लगाते और उग्रवादी अत्याधुनिक हथियारों से हवा में फायरर करते दिखाई दे रहे हैं। हमारी संस्था इस वीडियो क्लिप की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करते हैं।

एनबीए ने 12 राज्यों में जैव प्रबंधन समितियों को 45.05 लाख रुपये वितरित किए

एजेंसी। नई दिल्ली

राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने राज्य जैव-विविधता बोर्डों और केंद्रशासित प्रदेश जैव-विविधता परिषदों के जरिए लाभार्थियों के बीच 45.05 लाख रुपये वितरित किए। अब कुल रीच और लाभ साझाकरण (एबीएस) भुगतान 145 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार इस भुगतान से 10 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित 90 से अधिक जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) और आंध्र प्रदेश के 15 लाल चंदन किसानों को लाभ मिलेगा। इनमें तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और लद्दाख शामिल हैं।

जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाली कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा उन समुदायों को देती हैं, जो इन संसाधनों को संरक्षित करते हैं। इससे उनकी आजीविका में सुधार होता है और जैव विविधता की रक्षा तथा संरक्षण के लिए प्रेरणा भी मिलती है। एनबीए का राष्ट्रीय जैव-विविधता सम्मेलन और नागोया प्रोटोकॉल के तहत सुदूरवर्ती क्षेत्रों के संसाधनों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का एक और प्रयास है।

हंगामे के चलते 13 मिनट में स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही राहुल गांधी को बोलने नहीं देने पर विपक्ष ने किया विरोध

एजेंसी। नई दिल्ली

संसद के बजट सत्र के 9वें दिन सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने देने की मांग को लेकर कई बार बाधित होने के बाद अंत में अगले दिन पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों ने आठ सदस्यों के निलंबन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का अवसर न दिए जाने के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया। इस दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सदन में मौजूद रहीं। लोकसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के बाद विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण पहले

12 बजे तक और फिर 02 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 2 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने कांग्रेस सदस्य शशि थरूर को बजट पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया लेकिन थरूर ने पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की अपील की और अपनी सीट पर बैठ गए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वह एक घंटे पहले लोकसभा अध्यक्ष से मिले थे और उन्हें व्यक्तिगत रूप से बोलने का आश्वासन दिया गया था। बजट पर चर्चा से पहले कुछ मुद्दे उठाने की अनुमति मांगी थी, इसलिए अब स्पष्ट किया जाए कि उन्हें बोलने दिया जाएगा या नहीं। इस पर पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने कहा कि उनके पास राहुल गांधी का कोई नोटिस नहीं आया है और उन्हें यह भी मालूम नहीं कि उनका विषय क्या है। जब नोटिस आएगा तब चर्चा होगी, फिलहाल बजट पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा करते रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को समझाने की कोशिश की। रिजिजू ने कहा कि वह स्वयं विपक्ष की बैठक के दौरान अध्यक्ष के चैंबर में मौजूद थे। राहुल गांधी का बयान पूरी तरह सही नहीं है। अध्यक्ष ने कोई आश्वासन नहीं दिया था, बल्कि केवल यह कहा था कि यदि बातचीत सही ढंग से होगी तो सभी दलों के नेताओं को बोलने का अवसर मिलेगा।

यूआईडीएआई ने देशभर के एक करोड़ से ज्यादा बच्चों को किया बायोमेट्रिक अपडेट पूरा

नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने स्कूली बच्चों के आधार से जुड़ा बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। देशभर के 83,000 स्कूलों में पढ़ने वाले 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट पूरा कर लिया है। आईटी मंत्रालय ने बयान जारी कर इस मिशन मोड अभियान की जानकारी दी। यूआईडीएआई ने यह विशेष अभियान सितंबर 2025 में शुरू किया था। इस अभियान को यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस ऐप से जोड़ा गया। इससे स्कूलों को यह पता चल सका कि किन बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट बाकी हैं। इसके बाद स्कूलों में विशेष शिविर लगाए और बच्चों का अपडेट पूरा किया। मीडिया रिपोर्ट में यूआईडीएआई के नियमों के मुताबिक पांच साल से कम उम्र के बच्चों का आधार बनाते समय केवल फोटो, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और जन्म प्रमाण पत्र लिया जाता है। इस उम्र में बच्चों के फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतली पूरी तरह विकसित नहीं होती, इसलिए इन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जब बच्चा पांच साल और 15 साल की उम्र पार कर लेता है, तब आधार में फिंगरप्रिंट और आइरिस अपडेट कराना जरूरी होता है।

भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता : गुजरात के उद्योगों के लिए विकास का नया द्वार

एजेंसी। अहमदाबाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौता किया गया है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह समझौता विशेष रूप से गुजरात के उद्योगों के लिए विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगाए गए कड़े टैरिफ को लगभग 50 प्रतिशत से घटाकर करीब 18 प्रतिशत कर दिया है। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमतें अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगी और उनकी मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में गुजरात आज भारत का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बन चुका है। राज्य में टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल्स, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में मजबूत औद्योगिक आधार मौजूद है। इस व्यापार समझौते से इन सभी क्षेत्रों को नया प्रोत्साहन मिलेगा। इस समझौते का सबसे अधिक लाभ टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योग को मिलने की संभावना है।

बीजेपी के ये अच्छे दिन आरएसएस की वजह से ही आए: मोहन भागवत

एजेंसी। मुंबई

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी को लेकर बड़ी लकीर खींच दी है। 2024 के आम चुनाव में तत्कालीन अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम आरएसएस के बिना भी चुनाव में जीत सकते हैं। इसे लेकर संघ कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष फैल गया था। अब सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि बीजेपी के ये अच्छे दिन आरएसएस के चलते ही आए हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के लिए आरएसएस ने प्रतिबद्धता दिखाई थी और जिसने इसका साथ दिया,

उसे फायदा मिला। इस तरह उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि संघ के नेतृत्व में चले राम मंदिर आंदोलन का फायदा बीजेपी को चुनाव में भी मिला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भागवत ने साफ कर दिया कि बीजेपी के लिए आरएसएस का कितना महत्व रखता है। माना जा रहा है कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखने के मकसद से उन्होंने ऐसी बात कही है। इसके अलावा बीजेपी नेतृत्व के लिए भी यह एक संदेश है कि भले ही दल का विस्तार हो गया है, लेकिन उसका वैचारिक आधार अब भी आरएसएस ही है। बता दें आरएसएस और बीजेपी के संबंधों को लेकर अकसर सवाल उठते रहे हैं। आरएसएस की ओर से बीजेपी में किसी भी फैसले लेने के दावों को खारिज किया जाता रहा है। उसका कहना है कि हम संघ के कार्यकर्ता देते हैं, लेकिन उसके फैसलों में हमारा कोई दखल नहीं रहता। पीएम मोदी की एक अलग राजनीतिक पार्टी है बीजेपी। उसमें बहुत से स्वयंसेवक हैं, लेकिन वह संघ की पार्टी नहीं है। उसमें स्वयंसेवक हैं और वे अपना काम करते हैं।

चंद्रयान-4: इसरो को मिली बड़ी कामयाबी, खोज ली गई लैंडिंग की सुरक्षित जगह

एजेंसी। श्रीहरिकोटा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने अगले और अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण चंद्र मिशन चंद्रयान-4 की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसरो के स्पेस ऐप्लिकेशन सेंटर (एसएसी) ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उस सटीक स्थान की पहचान कर ली है, जहां चंद्रयान-4 को उतारा जाएगा। यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रयान-4 भारत का पहला रिटर्न मिशन होगा, जिसका लक्ष्य न केवल चांद पर उतरना है, बल्कि वहां से नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटना भी है। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर द्वारा भेजी गई हाई-रिजोल्यूशन तस्वीरों का गहन विश्लेषण करने के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लगभग

1 वर्ग किलोमीटर के एक सुरक्षित क्षेत्र का चयन किया है। इस अध्ययन को वैज्ञानिकों की एक विशेष टीम ने अंजाम दिया है, जिन्होंने लैंडिंग के लिए चार संभावित स्थलों की समीक्षा की थी। जांच के बाद एमएम-4 नामक स्थान को सबसे उपयुक्त पाया गया है। मिशन की चुनौतियां और विशेषताएं चंद्रयान-4 मिशन तकनीक और जटिलता के मामले में पिछले मिशनों से काफी आगे है। इस मिशन में प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ-साथ डिसेंटर और असेंडर मॉड्यूल शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसफर मॉड्यूल और रीएंट्री मॉड्यूल भी इस मिशन का हिस्सा होंगे। मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी और पत्थरों के नमूने एकत्र करना और उन्हें सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लाना है। यदि भारत इस मिशन में सफल रहता है, तो यह भविष्य के मानवयुक्त चंद्र मिशनों (गगनयान के अगले चरण) के लिए मील का पत्थर साबित होगा।लैंडिंग साइट की खासियत चुनी गई लैंडिंग साइट नॉविस माउंटेन पहाड़ी के पास स्थित है। पहाड़ी क्षेत्र के करीब होने के बावजूद, यह पैच काफी समतल है, जिससे लैंडर को नुकसान पहुंचने का खतरा न्यूनतम है।

उत्तर रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण को मंजूरी, 421.41 करोड़ होंगे खर्च

नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने उत्तर रेलवे के तहत सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 421.41 करोड़ रुपये की दो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। इनका उद्देश्य हाई डेंसिटी नेटवर्क (एचडीएन) और हाईली यूज्ड नेटवर्क (एचयूएन) मार्गों पर रेल संरक्षा को और मजबूत करना तथा परिचालन दक्षता में वृद्धि करना है। स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत दिल्ली और अंबाला मंडल के कुल 34 स्टेशनों पर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह कार्य उन स्टेशनों पर किया जाएगा, जहां स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली 'कवच' को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। आधुनिक सिग्नलिंग और कवच तकनीक के समन्वय से व्यस्त रेल मार्गों पर सुरक्षित, सुचारु और उच्च क्षमता वाला ट्रेन संचालन सुनिश्चित होगा। रेल मंत्रालय के अनुसार दिल्ली मंडल में एचडीएन/एचयूएन मार्गों पर स्थित 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिस पर 292.24 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEUTICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

ख़ास ख़बर

संसद में विपक्ष को गंभीर मुद्दे उठाने नहीं दिया जा रहा : मनीष तिवारी

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र में लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित होने पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि देश के सामने बेहद अहम मुद्दे हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। तिवारी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार ढांचे पर संयुक्त बयान और अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकारी आदेश, जिसमें कहा गया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हमारी विदेश और आर्थिक नीति की स्वायत्तता पर रणनीतिक असर डालते हैं। इसके अलावा सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी अहम है, लेकिन विपक्ष को इन विषयों पर चर्चा करने से रोका गया। कांग्रेस सांसद तिवारी ने कहा कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार की जिद के कारण सर्वोच्च विधायी संस्था को अप्रासंगिक बना दिया गया है। सरकार ने अतिरिक्त प्रयास कर यह सुनिश्चित किया है कि संसद अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ हो जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट रूम में वकील पर हमले को बताया 'गुंडाराज'

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में सोमवार को एक वकील ने तीस हजारी कोर्ट के कोर्ट रुम में अपने ऊपर हमले की शिकायत की। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे गुंडाराज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कानून का राज खत्म हो गया है। चीफ जस्टिस ने वकील को दिल्ली उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से इसकी शिकायत करने को कहा। दरअसल, दिल्ली के एक वकील ने चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष कहा कि 7 फरवरी को वे एक केस में तीस हजारी कोर्ट के जज हरजीत सिंह पाल की कोर्ट में आरोपितों की ओर से पेश हुए थे। इसी दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने कई गुंडों के साथ हमला कर दिया। उस समय जज अपने सभी स्टाफ के साथ कोर्ट रुम में मौजूद थे। घटना का विवरण बताने के बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या इस मामले की शिकायत दिल्ली उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय से की गई है, तब वकील ने कहा कि नहीं। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दिल्ली उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से इस संबंध में शिकायत कीजिए। इस शिकायत पर वे प्रशासनिक स्तर पर फैसला करेंगे।

डीडीए पार्क में दो लोगों पर चाकू से हमला, एक की मौत

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके स्थित डीडीए पार्क में रविवार शाम को अज्ञात हमलावरों ने दो युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में एक नाबालिग की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। वारदात के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 6:37 बजे मोती नगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक नाबालिग को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है। उसके दाहिने कंधे के नीचे चाकू से वार किया गया था। इसके कुछ देर बाद शाम 7:50 बजे एक अन्य घायल युवक की सूचना मिली। उसकी पहचान मोहम्मद दानिश (25) के रूप में हुई है। जिसे पीठ में चाकू मारा गया था। पहले उसे आचार्य भिक्षु अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पार्क को घेर लिया और जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आपसी विवाद या रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, हालांकि हत्या के पीछे की असली वजह जांच पूरी होने के बाद साफ हो सकेगी। पुलिस आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

अधिकांश श्रमिकों को उम्मीद, नई श्रम संहिताओं से बेहतर होंगी कार्य स्थितियां: सर्वेक्षण

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। देश में चार नई श्रम संहिताओं के लागू होने से कार्यबल को मजबूत संरक्षण, नियमों के सरल अनुपालन और कामकाज की बेहतर स्थितियां मिलने की उम्मीद है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक करीब 60 फीसदी श्रमिकों का मानना है कि इन नयी संहिताओं के लागू होने से उनकी कार्य स्थितियों में समग्र सुधार होगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को नोएडा स्थित वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) के सर्वेक्षण के हवाले से यह जानकारी दी है। सर्वेक्षण से श्रमिकों और नियोक्ताओं द्वारा श्रम संहिताओं के व्यापक समर्थन की पुष्टि हुई है। इस अध्ययन में श्रम सुधारों के कार्यान्वयन के माध्यम से कार्य स्थितियों, सामाजिक सुरक्षा और शिकायत निवारण पर सकारात्मक धारणाओं को उजागर किया गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक श्रम संहिता को श्रम संरक्षण को मजबूत करने, संबंधों को आधुनिक बनाने और अनुपालन को सरल बनाने के रूप में देखा जाता है। सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों के अनुसार 63 फीसदी श्रमिकों को काम के घंटों के बेहतर नियमन और 60 फीसदी को अवकाश के प्रावधानों में सुधार की उम्मीद है। करीब 66 फीसदी श्रमिकों का मानना है कि सुरक्षा और परिवहन से जुड़ी अनिवार्यताओं से महिला कर्मचारियों को बेहतर संरक्षण मिलेगा। आय सुरक्षा के मोर्चे पर 64 फीसदी श्रमिकों को वेतन में पारदर्शिता और 54 फीसदी को समय पर भुगतान की उम्मीद है, जबकि सामाजिक सुरक्षा के संबंध में 68 फीसदी श्रमिकों ने ई-श्रम और कल्याण बोर्ड के माध्यम से सुविधाओं तक आसान पहुंच की सराहना की है। इसके साथ ही 63 फीसदी श्रमिकों का मानना है कि नयी संहिताओं से अनुबंध, प्रवासी और गिग या अस्थायी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाना और भी आसान हो जाएगा। 76 फीसदी नियोक्ताओं ने कार्यबल के लचीलेपन को कारोबार के लिए महत्वपूर्ण माना है। नियोक्ताओं के दृष्टिकोण से करीब 64 फीसदी का मानना है कि 'निश्चित अवधि का रोजगार' उनके कारोबारी मॉडल के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही 64 फीसदी नियोक्ताओं को उम्मीद है कि वेतन भुगतान के समयबद्ध नियम कार्यस्थल पर अनुशासन को बढ़ावा देंगे। सर्वेक्षण के अनुसार करीब 73 फीसदी नियोक्ताओं ने लंबी अवधि में नियमों के अनुपालन के सरल होने का अनुमान जताया है, जबकि लगभग 62 प्रतिशत नियोक्ता इस बात पर सहमत हैं कि नयी व्यवस्था से श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा। इसके अलावा करीब 73 फीसदी नियोक्ताओं का मानना है कि नई श्रम संहिताओं से नियमों के अनुपालन की जटिलताएं कम होंगी और प्रक्रिया सरल हो जाएगी। यह शोध कुल 6,435 लोगों के नमूने (सैंपल) पर आधारित है, जिसमें 5,720 श्रमिक और 715 नियोक्ता शामिल थे।

मंत्रालय के मुताबिक श्रम संहिताओं का कार्यान्वयनः धारणा आधारित विश्लेषण' शीर्षक वाले इस अध्ययन से पता चलता है कि इन सुधारों को लेकर श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच विश्वास और सकारात्मकता बढ़ी है। ये संस्थान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ''ये निष्कर्ष श्रम संहिताओं के उस उद्देश्य को रेखांकित करते हैं, जिसका लक्ष्य सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक कार्य और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 21 नवंबर को 4 श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया था और 31 दिसंबर, 2025 को नियमों के मसौदे पर सुझाव मांगे थे। सरकार का इरादा एक अप्रैल, 2026 से इन चारों संहिताओं को पूरी तरह प्रभावी बनाने का है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रेया नारायण ने क्यों कहा-'उसने बुलाया था

लोकतंत्र की शान

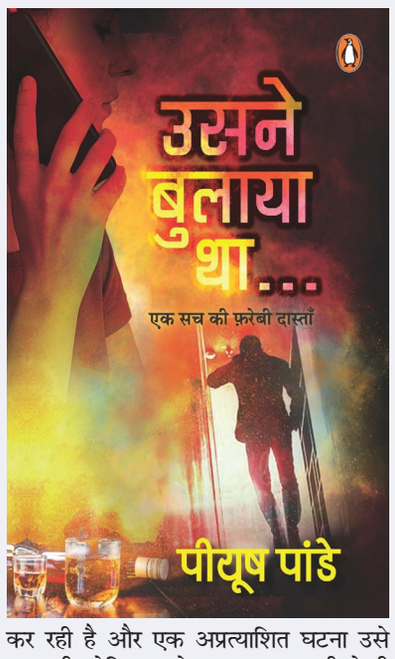

'साहब,बीवी और गैंगस्टर', 'सुपरनानी', 'लाल रंग', 'रॉकस्टार' और 'कुछ करिए' जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी बॉलीवुड अभिनेत्री श्रेया नारायण ने हाल में अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर एक वीडियो जारी कर कहा-उसने बुलाया था। इस वीडियो के आते ही कई लोगों को कौतूहल हुआ कि श्रेया को किसने और कहाँ बुलाया था। हालांकि, वीडियो के अगले ही हिस्से में साफ हो गया कि 'उसने बुलाया था' दरअसल लेखक पीयूष पांडे के क्राइम फिक्शन का नाम है, और श्रेया ने इस सनसनीखेज कहानी पर केंद्रित किताब को लेकर सनसनीखेज अंदाज में ही वीडियो पोस्ट किया। श्रेया ने इस अनूठे वीडियो को लेकर कहा, "मैं 'उसने बुलाया' था की कहानी को सबसे पहले पढ़ने वालों में हूं। ये देश की हर लड़की से जुड़ी एक बहुत जरुरी कहानी है। ये एक क्राइम फिक्शन है, लेकिन मैं इसमें लोगों की उत्सुकता पैदा करना चाहती थी, और इसलिए मैंने थोड़ा सनसनीखेज स्टाइल में वीडियो बनाया। इस उपन्यास पर फिल्म या वेबसीरिज बनने की पूरी संभावना है, और इसलिए मैं चाहती थी कि इसे पढ़ा जाए।" 'उसने बुलाया था' एक ऐसी युवती की कहानी है जो मनोविज्ञान (साइकोलॉजी) में शोध कर रही है और एक अप्रत्याशित घटना उसे अपराधी घोषित करते हुए अदालत की देहरी पर पहुंचा देती है, जहां रोज होने वाले खुलासे इसे देश का सबसे सनसनीखेज मामला बना देते हैं। दिलचस्प ये कि पत्रकार-लेखक पीयूष पांडे जिस वक्त इस कहानी पर काम कर रहे थे, तब श्रेया नारायण ने ही उनसे कहा कि कहानी पर फिल्म बनने की पूरी संभावना है, इसलिए पहले स्क्रीनप्ले लिखा जाना चाहिए। पीयूष पांडे कहते हैं,"मेरी कहानी पर कई दिग्गजों ने भरोसा जताया था। 'नाम शबाना' और 'द डिप्लोमेट' जैसी फिल्म के निर्देशक शिवम नायर को मैंने प्लॉट सुनाया तो उन्होंने शानदार कहा। फिर, 'चक दे' जैसी कई फिल्में लिख चुके जाने माने स्क्रिप्ट राइटर जयदीप साहनी ने पूरी कहानी सुनने के बाद शानदार कहा तो हौसला बढ़ गया। मैंने पहले स्क्रीनप्ले ही लिखा था। और संयोग से सिंगापुर फिल्म बाजार में कहानी पर फिल्म बनाने के इच्छुक निर्माता भी मिल गए लेकिन मैं उस वक्त एक बड़े न्यूज चैनल में था और तय समय पर डायलॉग समेत पूरा स्क्रीनप्ले उन्हें नहीं दे सका।" 2018 में श्रेया नारायण ने ही सिंगापुर में इस कहानी को कई निर्माताओं के बीच पिच किया था। पीयूष कहते हैं,"फिल्म जब बनेगी तब बनेगी लेकिन मैंने एक जरुरी कहानी पर उपन्यास लिख दिया है।" 'उसने बुलाया था' को पेंगुइन स्वदेश ने प्रकाशित किया है। पीयूष पांडे इससे पहले अभिनेता मनोज बाजपेयी की बायोग्राफी लिखकर चर्चा में आए थे। मनोज बाजपेयी की बायोग्राफी हिन्दी और अंग्रेजी में पेंगुइन रेंडम हाउस ने प्रकाशित की है, जबकि इसके गुजराती और मराठी संस्करण भी आ चुके हैं।

नौकरी के बदले जमीन मामले में तेजस्वी यादव राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। लैंड फॉर जॉब के मनी लांड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सोमवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव ने आरोपों से इनकार करते हुए आरोपों का सामना करने की बात कही। इस मामले में 6 अगस्त, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपितों के खिलाफ पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। उसके बाद से लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति का इंतजार था। 14 मई, 2024 को ईडी ने लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने संबंधी अनुमति पत्र कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 18 सितंबर, 2024 को ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में 96 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किये गए हैं। कोर्ट ने 7 मार्च, 2024 को ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, सीमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में ईडी के पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने केस दर्ज किया था। सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2023 को बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। कोर्ट ने 22 सितंबर, 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 3 जुलाई, 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 27 फरवरी, 2023 को इन तीनों आरोपितों समेत सभी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 7 अक्टूबर, 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

द स्टेट्समैन विंटेज एवं क्लासिक 59 वाँ कार रैली सम्पन्न

लोकतंत्र की शान

संवाददाता नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में रविवार को द स्टेट्समैन विंटेज एवं क्लासिक कार रैली के 59वें संस्करण का भव्य आयोजन किया गया।इस ऐतिहासिक और दुर्लभ कारों की इस प्रतिष्ठित रैली को दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना एवं पोटाला प्रसाद नायडू,राष्ट्रीय ओबीसी (ज्योतिबा फुले) अध्यक्ष ने बाराखंभा रोड स्थित द स्टेट्समैन हाउस से झंडी दिखाकर रवाना किया।इस अवसर पर द स्टेट्समैन लिमिटेड के अध्यक्ष आर. पी. गुप्ता,संपादक एवं प्रबंध निदेशक रवींद्र कुमार तथा निदेशक विनीत गुप्ता उपस्थित रहे।रैली की थीम "युग की महारानियाँ" रखी गई थी, जिसमें ऐतिहासिक कालखंड की प्रतिष्ठित कारों का प्रदर्शन किया गया।इस रैली में 100 से अधिक विंटेज और क्लासिक वाहन शामिल हुए। प्रमुख आकर्षणों में 1906 की रेनॉल्ट,1936 रोल्स रॉयस,1938 मर्सिडीज और एडलर,1926 स्टुडबेकर, 1937 वोल्सली,1932 बेबी ऑस्टिन,1919 सिट्रोएन, 1913 स्टोएवर तथा 1912 स्टैंडर्ड कोवेंट्री सहित अनेक दुर्लभ वाहन शामिल रहे।दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि दिल्ली में ऐसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए,जिससे लोग देश की विरासत और इतिहास से जुड़ सकें। रैली के तहत वाहनों ने शहर में ड्राइव किया और दोपहर 12:30 बजे इंडिया गेट के समीप मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम पहुँचीं। वहीं दोपहर 3 बजे पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में कार प्रेमियों, महिलाओं,बच्चों और बुजुर्गों ने कार्यक्रम में भाग लिया और ऐतिहासिक वाहनों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। द स्टेट्समैन विंटेज एवं क्लासिक कार रैली भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मोटरिंग आयोजनों में से एक है।इसकी शुरुआत वर्ष 1964 में दिल्ली में हुई थी और 1968 में कोलकाता में इसका आयोजन आरंभ हुआ था।यह रैली प्रतिवर्ष आयोजित होती है और विंटेज कार मालिकों को अपनी ऐतिहासिक मशीनों को आधुनिक सड़कों पर चलाने का अवसर प्रदान करती है।रैली का समापन मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ,जिसने राजधानी वासियों को बीते युग की उत्कृष्ट कारीगरी और मोटरिंग विरासत की जीवंत झलक प्रदान की।

डॉ. अखिलेश दास गुप्ता इंस्ट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में फैकल्टी और स्टूडेंस के साथ कॉल फोर हार्मनी इंटरैक्शन प्रोग्राम का भव्य आयोजन

लोकतंत्र की शान

आज दिनाँक 09.02.2026 को डॉ. अखिलेश दास गुप्ता इंस्ट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में फैकल्टी और स्टूडेंस के साथ कॉल फोर हार्मनी इंटरैक्शन प्रोग्राम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री चंद्र वाधवा जी, श्री गोपाल कृष्ण, (भारतीय प्रशासनिक सेवा) और श्री धनराज, (भारतीय कॉर्पोरेट सेवा) मुख्य अतिथि थे। अन्य गणमान्य व्यक्तियों में डॉ. विजय धीर, डायरेक्टर कॉर्डिनेशन, प्रो. डॉ. निरंजन भट्टाचार्य, डायरेक्टर, श्री बी.एम.के. गुप्ता, डायरेक्टर फाइनान्स, श्रीमती पंखुड़ी अग्रवाल, असिस्टेंट डायरेक्टर (एच. आर.), समस्त विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर फैकल्टी एवं स्टाफ उपस्थित थे। ये कार्यक्रम माननीय चेयरपर्सन मैम श्रीमती अलका दास गुप्ता जी, माननीय अध्यक्ष महोदय श्री विराज सागर दास जी, माननीय उपाध्यक्ष सुश्री सोनाक्षी दास जी और माननीय उपाध्यक्ष श्रीमती देवांषी दास जी के सकुशल मार्गदर्शन और समर्थन के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रो. डॉ. निरंजन भट्टाचार्य ने अतिथियों को संस्थान की उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया तथा समरसता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने संगीत का उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे संगीत में विभिन्न सुर एक ही लय में मिलकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र-चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक - में समन्वय और समरसता आवश्यक है। इस अवसर पर ए.डी.जी.आई.पी.एस. के छात्रों ने अतिथियों के साथ प्रश्न-उत्तर कर अपनी जिज्ञासाएँ का हल प्राप्त किया। अतिथियों ने छात्रों को पंच परिवर्तन के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्यों के पालन, आत्मनिर्भरता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया। यही समरस दृष्टि विकसित भारत के निर्माण की सच्ची शक्ति है।

वर्तमान बजट प्रदेश और देश को विकसित बनायेगा: केशव प्रसाद मौर्य

लोकतंत्र की शान

» यूनियन बजट 2026-27 व्यापारी सम्मेलन

लखनऊ।भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ, लखनऊ महानगर के तत्वावधान में आज विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में आयोजित ' यूनियन बजट 2026-27 व्यापारी सम्मेलन' में मुख्य अतिथि केशव प्रसाद मौर्य उप-मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि किसी भी बजट का उद्देश्य, देश को दीर्घकालिक प्रगति के रास्ते पर ले जाने का होता है। आज भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। उन्होंने कहा कि हम विश्व के तकनीकी स्तर पर श्रेष्ठ देशों के साथ समझौता कर रहें हैं। आज इस बजट को देखें तो हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने व्यापरियों से अपील की, कि हम स्वदेशी ही बेचेंगे और स्वदेशी ही खरीदेंगे। उन्होंने मंच से नारा दिया कि 'जब बाजार जायेंगे माल स्वदेशी ही लायेंगे'। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी ना हो तो क्या कोई उत्तर प्रदेश में व्यापार करना चाहेगा क्या ? प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब व्यापारी पलायन कर रहे थे क्योंकि ना पैसा सुरक्षित था ना परिवार। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश के 25 करोड लोगों की सुरक्षा की गारंटी है। प्रधानमंत्री जी द्वारा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के करीब है और और दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ओपन ट्रेड डील के माध्यम से अमेरिका यूरोप और अन्य देशों के साथ व्यापार के रास्ते खुले हैं। देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी औद्योगिक क्रांति आ चुकी है और बहुत बड़े स्तर पर निवेश आ रहा है। लखनऊ के व्यापारियों का माल भी विदेश में जाए इसके लिए आप सभी के पास बड़ा अवसर है इसके लिए आप सभी तैयारी करें। डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। पहले वैट के नाम पर व्यापारियों का बड़ा उत्पीड़न होता था लेकिन वेट की जगह जीएसटी आया इसमें पहले तो दर ज्यादा थी लेकिन आज जीएसटी दर इतनी कम कर दी गई की व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करें और ईमानदारी से टैक्स दें। उसका परिणाम है कि आज देश आत्मनिर्भर भारत बन रहा है और आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार आज सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। आज विपक्षी दल व्यापारी का मतलब भाजपाई ही समझते है और हमें इस पर गर्व है आज प्रतिकूल स्थिति में आप कमल का फूल खिला रहे हैं और जब प्रतिकूल स्थिति थी तब भी आपने कमल का फूल का साथ दिया। आज केंद्रीय बजट पर परिचर्चा के अवसर पर आप सभी से आवाहन करता हूं कि प्रधानमंत्री जी की अपील के अनुसार हम स्वदेशी ही खरीदेंगे और स्वदेशी ही बेचेंगे। प्रयागराज कुंभ में और अयोध्या, काशी, मथुरा व अन्य तीर्थ स्थलों पर 100 करोड़ से अधिक लोग दर्शन के लिए आए जो कुछ ना कुछ खरीद कर ले गए। समाजवादी पार्टी सरकार के समय में प्रदेशवासियों और व्यापारियों की सुरक्षा खतरे में थी। इनका कार्य था कि फूट डालो और राज करो। प्रधानमंत्री जी ने आजादी के 100 साल पूरा होने पर 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य रखा है तो समझ लीजिए कि अगले 21 साल तक प्रदेश में ना समाजवादी पार्टी और ना देश में कांग्रेस के आने की संभावना है क्योंकि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाना पीड़ीए के विजन और बूते की बात नहीं है। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। राहुल गांधी जी के संसद में घटिया विचार आपने सुने है जो निरंतर सासद की निष्पक्ष कार्यवाही में बाधा बनते हैं और वैसा ही रास्ता आज समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में दिखाया। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समय ऐसा हो हल्ला कर रहे थे कि जैसे छात्र संघ का चुनाव हो। टैक्स के नाम पर शोषण और उत्पीड़न बंद हुआ है। मोदी जी ने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और किसी ने भी बेईमानी करके खाया है तो उसकी जांच करा कर वसूल करके देश की भलाई में वापस लगाऊंगा। जैसे प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी है वैसे ही अगडी, पिछडी और अनुसूचित जाति की त्रिवेणी भारतीय जनता पार्टी में है। हम सबका साथ और सबका विकास करते हैं जिसने वोट नहीं दिया उनको भी आवास आयुष्मान कार्ड और सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 2027 में लखनऊ की सभी सीटों पर भी कमल खिलेगा और 2027 में हमें अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। 2027 में 325 से भी ज्यादा सीट हासिल करके उससे भी बड़ी विजय प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ाना है और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करना है। वह सैफई वापस जाए लखनऊ में इनकी जरूरत नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में जनता को गुमराह किया था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान और आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान की पुजारी है और आरक्षण की समर्थक है। 2024 लोकसभा चुनाव में यह भ्रम फैलाकर कुछ सीटें ज्यादा जरुर हासिल कर ली लेकिन उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में भी हमने बड़ी विजय हासिल की है। यूनियन बजट 2026-27 व्यापारी सम्मेलन ' के अति विशिष्ट अतिथि नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने अपने संबोधन में वर्तमान बजट को 2047 के विकसित और संस्कृति से समृद्ध विकसित भारत की नींव बताते हुए बजट को आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक नोएडा पंकज सिंह ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत का सबसे हाई ग्रोथ रेट चल रहा है, 2047 का एक नया भारत होगा। आज इस बजट के माध्यम से कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है, बजट में दस हजार करोड़ का ग्रोथ फण्ड भी रखा गया है। कैपिटल एक्सपेंडेशन में 9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। डिफेंस में 7.8 लाख करोड़ दिए गए हैं। इस बजट से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार, संस्कृति से समृद्ध भारत और विकसित भारत 2047 तक बनाने के मिशन पर कार्य कर रही है। यूनियन बजट 2026-27 व्यापारी सम्मेलन में लखनऊ भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान बजट के माध्यम से देश का व्यापारी वर्ग प्रदेश और देश को विकसित बनाने की दिशा में अग्रणी रहेगा। कार्यक्रम में व्यापारी सम्मेलन के संयोजक और भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अभिषेक खरे ने उत्तर प्रदेश के उद्यमी एवं व्यापारी समाज की सुरक्षा, राहत एवं व्यापारिक सुगमता हेतु एक 5 सूत्रीय ज्ञापन मुख्य अतिथि को सौंपते हुए कहा कि व्यापारी वर्ग हमेशा से भाजपा के साथ रहा है और आगे भी भाजपा के ही साथ रहेगा। उन्होंने सभी से स्वदेशी वस्तुओं को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग ने बताया कि इस अवसर पर विनीत अग्रवाल शारदा प्रदेश संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश, मनीष गुप्ता सह-संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ, सुधीर हलवासिया, अजय त्रिपाठी मुन्ना, संदीप बंसल, घनश्याम अग्रवाल गुड्डा, टिंकू सोनकर सहित राजधानी के तमाम व्यापारी संगठनों से व्यापारी उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

रजिस्ट्री कराते समय हो रही है असुविधाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहाः हसनपुर : सोमवार को तहसील बार एसोसिएशन हसनपुर के पूर्व अध्यक्ष तथा रालोद के क्षेत्रीय महासचिव मुजाहिद चौधरी एडवोकेट ने उत्तर प्रदेश के सब रजिस्ट्री कार्यालयों में लेख पत्रों के निष्पादन व रजिस्ट्री के दौरान आधार वेरिफिकेशन की नई व्यवस्था के कारण हो रही दुश्वारियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है,उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन प्रेषित कर बैनामों /लेख पत्रों के सुगमता पूर्वक निष्पादन व रजिस्ट्री हेतु हाथों की उंगलियों व अंगूठे के अतिरिक्त चेहरे और आंखों को स्कैन करने की व्यवस्था लागू करने की मांग की है । उन्होंने कहा कि विक्रय धन का भुगतान होने के बाद,समय पर बैनामों की रजिस्ट्री ना होने के कारण जनता को असीम चिंता और तनाव का सामना करना पड़ रहा है। तथा रजिस्ट्री विभाग को भी निर्धारित समय- सीमा में स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फीस का टारगेट पूरा करने में बहुत कठिनाई हो सकती है। पत्र की प्रति आई.जी. रजिस्ट्रेशन, मंडल आयुक्त मुरादाबाद तथा जिलाधिकारी अमरोहा को प्रेषित कर इस समस्या के शीघ्र निराकरण की मांग की गई है l

शराब के आदी बैंड में काम करने वाले ने लगाई फांसी,मौत

लोकतंत्र की शान : शाहाबाद हरदोई। कोतवाली क्षेत्र के नरहाई गांव में एक अधेड़ ने शराब के लिए पैसे पर न मिलने के कारण आम के बाग में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली ।सूचना पाकर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्राम नरहाई निवासी राम रूप 50 वर्ष पुत्र बालक राम शराब पीने का आदी था। इसी शराब पीने के कारण उसका विवाह नहीं हुआ। दोपहर में उसने अपनी मां से पैसे मांगे। मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने मां को डराने की वजह से पड़ोस के ही विजय के आम के बाग में दुपट्टे से फांसी लगाने की नौटंकी करने का प्रयास किया लेकिन धोखे से उसके फांसी लग गई और उसकी मौत हो गई।मृतक बारात में बाजा बजाने का कार्य करता था।सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

स्वच्छता मिशन के नाम पर करोड़ों का दुरुपयोग आरआरसी सेंटर बने बदहाली की मिसाल

लोकतंत्र की शान : सीतापुर। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)अन्तर्गत जनपद में करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए आर आरसी सेंटर (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) आज स्वयं गंदगी अव्यवस्था और लापरवाही का प्रतीक बन चुके हैं।वर्षों बीत जाने के बावजूद न तो गांवों में कूड़ा उठाने की समुचित व्यवस्था है और न ही कूड़ा ढोने के लिए वाहन या मजदूर उपलब्ध हैं। यह आरोप किसान मंच के जिला संयोजक एवं आज़ाद अधिकार सेना के जिला अध्यक्ष नवल किशोर मिश्रा ने जारी बयान में लगाया। उन्होंने कहा कि-"स्वच्छता मिशन को पंचायत विभाग ने एक गंभीर जनहित योजना की बजाय केवल भवन निर्माण और कमीशन बाजी का माध्यम बना दिया। जनता के टैक्स के पैसों से कूड़ा घर (आरआरसी सेंटर) तो बना दिए गए लेकिन उनके संचालन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसका खामियाजा ग्रामीण जनता को भुगतना पड़ रहा है।उन्होंने बताया कि गांवों में कूड़ा सड़कों खेतों और खाली जमीनों पर जमा है जिससे बदबू मच्छरों और संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कई स्थानों पर आर आर सी सेंटर खुद कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं जो योजना की असफलता को उजागर करता है। नवल किशोर मिश्रा ने कहा कि इस गंभीर विषय को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है जिसमें स्वच्छता मिशन के तहत हुए खर्च कूड़ा प्रबंधन की विफलता और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का उल्लेख किया गया है। उन्होंने मांग की कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत हुए करोड़ों रुपये के खर्च की निष्पक्ष जांच कराई जाए निष्क्रिय आरआर सी सेंटरों को तत्काल क्रियाशील बनाया जाए और दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। किसान मंच और आज़ाद अधिकार सेना ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सुधार नहीं किया गया तो संगठन जनहित में आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर होगा।

मशीयत फातिमा ने देश में यूपी टीम से खेलकर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नाम रोशन किया

लोकतंत्र की शान : रामपुर। समाजसेवी फ़रहत अली खां की बेटी ने मशीयत फातिमा ने देश में यूपी टीम से खेल कर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर विशेषकर रामपुर और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर हुआ जोरदार स्वागत। समाज सेवी नदीम खान ने फरहत अली खान के निवास बजोड़ी टोलपर बेटी मशीयत फातिमा को शाल और ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया। मशीयत फातिमा ने अंडर 14 हॉकी टीम यूपी का प्रतिनिधित्व 2 से 7 जनवरी ग्वालियर मध्यप्रदेश में किया था। मशीयत फातिमा रामपुर से पहली बालिका हॉकी खिलाड़ी और मैडल जीतने वाली बालिका हैं। इस अवसर नगर के संभ्रांत लोग और वरिष्ठ खिलाड़ी मौजूद रहे। जिसमें उस्मान नूर खान, साजिद खान,यूसुफ खान, दानिश खान मुख्तार खान, रेहान खान, आसिम खान, वासे, खालिद, इमरान उर रहमान खान, जुनैद खान, सलीम मोहम्मद खान, आरिफ खान, फरीद, फूल खान, बाकर खान, गुलफान अब्बासी, खुर्रम खान,राजू भाई, अय्यूब खान, शाबाहत अली खान , मीडिया बन्धु के अतिरिक्त बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही।

विद्युत पोल तोड़ने वाले कार चालक पर रिपोर्ट दर्ज

लोकतंत्र की शान : शाहाबाद हरदोई। कोतवाली छेत्र के मोहल्ला रामनगर कॉलोनी के निकट 7 फरवरी की रात एक कार चालक द्वारा विद्युत् पोल तोड़े जाने की घटना को लेकर विद्युत् विभाग के अवर अभियंता ने आरोपी के विरुद्ध कोतवाली पुलिस को लिखित तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू की है। 33/11 केवी विद्युत् उपकेंद्र इस्लामगंज के अवर अभियंता दीपक कुमार के अनुसार 7 फरवरी की रात करीब 11.30 बजे यूपी 30 बीए 7887 के चालक ने तेज गति लापरवाही से वाहन चलाते हुए ग्यारह हजार लाइन के पोल में टक्कर मार दी जिससे पोल टूट गया। छेत्र की विद्युत् आपूर्ति ध्वस्त होने के साथ बाड़ा हादसा भी हो सकता था। अवर अभियंता की लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

कोहरा बना हादसे का कारण ट्रैक्टर ट्राली से टकराई प्राइवेट यात्री बस कोई हताहत नहीं

लोकतंत्र की शान : मिहींपुरवा बहराइच/मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जालिम नगर पुल पर प्राइवेट बस ट्रैक्टर ट्राली से टकराई। पुलिस ने हाइड्रा मंगा कर रास्ते को कराया बहाल। इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नानपारा लखीमपुर हाईवे के सीमा पर स्थित जालिम नगर पुल पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस नंबर UP-15 FT O306 घने कोहरे के कारण आगे जा रहे ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। अचानक हुई इस दुर्घटना से बस में बैठी यात्रियों में हड़कंप मच गया। इस दुर्घटना में बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने बस यात्रियों को सुरक्षित बस से उतार कर अन्य वाहन से उन्हें गंतव्य स्थान पर रवाना किया। जानकारी के अनुसार प्राइवेट बस दिल्ली से चलकर बहराइच की तरफ जा रही थी तभी सुबह घने कोहरे के कारण आगे जा रही ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई किंतु बस में बैठे यात्रियों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई। चौकी प्रभारी जालिम नगर दिवाकर मिश्रा ने बताया घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। प्राइवेट यात्री बस ट्रैक्टर ट्राली से पुल पर टकरा गई। वाहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसलिए फिलहाल एक तरफ वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया गया है। हाइड्रा मंगाया गया है कुछ देर बाद आवागमन पूरी बहाल कर दिया गया है।

शिया वक़्फ़ बोर्ड में महाघोटाला: इबादतगाहें बिकीं, दलाल मालामाल

हज़ारों करोड़ की वक़्फ़ संपत्तियों की लूट! है HTF का आरोप-बोर्ड बना रियल एस्टेट गिरोह

लोकतंत्र की शान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड में फैले कथित भ्रष्टाचार, लूट और भूमाफिया गठजोड़ के खिलाफ शिया मुस्लिम संगठन हैदरी टास्क फोर्स (HTF) ने रविवार, 8 फरवरी को लखनऊ के ऐतिहासिक छोटा इमामबाड़ा, हुसैनाबाद में दिनभर का ज़ोरदार धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान HTF ने केंद्र सरकार से वक़्फ़ बोर्ड के खिलाफ CBI जांच कराए जाने और उत्तर प्रदेश सरकार से मौजूदा शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड को तत्काल भंग करने की मांग की। संगठन का आरोप है कि शिया समुदाय की हज़ारों करोड़ रुपये की वक़्फ़ संपत्तियों को सुनियोजित तरीके से रिकॉर्ड से गायब कर भूमाफियाओं के हाथों बेच दिया गया। HTF नेताओं का कहना है कि वक़्फ़ बोर्ड अब धार्मिक संपत्तियों का संरक्षक न रहकर ज़मीनों की दलाली करने वाला गिरोह बन चुका है। धरने को संबोधित करते हुए HTF के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ने आगा ने कहा कि वक़्फ़ बोर्ड की मिलीभगत से शिया समुदाय की कई ऐतिहासिक और धार्मिक संपत्तियां बेची जा चुकी हैं। इनमें मस्जिद शाहदरा (मोहन रोड), कर्बला अब्बास बाग (हरदोई रोड), मोती मस्जिद (मेहताब बाग–शीश महल), रानी रसूलपुर (गोलागंज), वक़्फ़ अहमदी बेगम और वक़्फ़ अच्छे मिर्ज़ा (औरंगाबाद–अमौसी) जैसी महत्वपूर्ण संपत्तियां शामिल हैं।

HTF के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज़ीशान ज़ैदी ने आरोप लगाया कि केवल मोती मस्जिद क्षेत्र की वक़्फ़ संपत्ति, जिसकी अनुमानित कीमत 300 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है, उसे अवैध रूप से बेच दिया गया। उन्होंने कहा कि इस खुले भ्रष्टाचार से न सिर्फ शिया समाज को गहरी चोट पहुंची है, बल्कि उस राज्य सरकार की साख पर भी सवाल खड़े होते हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करती है। HTF नेताओं ने दावा किया कि यदि संगठन समय पर हस्तक्षेप न करता तो और भी वक़्फ़ संपत्तियां बिक चुकी होतीं। संगठन के विरोध और स्थलीय निरीक्षणों के चलते रौज़ा हज़रत क़ासिम, न्यू हैदराबाद, कर्बला अजीमुल्लाह खान जैसी संपत्तियों को बचाया जा सका। वहीं वर्ष 2025 में कर्बला तालकटोरा में हो रहे अवैध निर्माण को भी HTF ने रुकवाया। HTF के महासचिव ज़ैगम ज़ैदी ने आरोप लगाया कि बोर्ड के चेयरमैन अली ज़ैदी बार-बार विदेश यात्राएं कर रहे हैं और वक़्फ़ संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धन को विदेशों में निवेश किया जा रहा है। उन्होंने इन यात्राओं और धन के स्रोतों की निष्पक्ष जांच की मांग की। धरने में मौजूद HTF के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ज़फ़रुल हसन, नदीम नक़वी और नक़ी ज़ैदी ने कहा कि वक़्फ़ बोर्ड केवल उन्हीं मामलों में आवाज़ उठाता है जहां उसे हिस्सेदारी नहीं मिलती, जबकि बड़ी रकम के लेन-देन वाले मामलों में बोर्ड पूरी तरह खामोश रहता है। अंत में HTF के प्रदेश अध्यक्ष हैदर रिज़वी ने विभिन्न स्थानों पर कब्रों की ऊँचे दामों पर बिक्री की भी उच्चस्तरीय जांच की मांग की। संगठन का आरोप है कि लखनऊ स्थित इमामबाड़ा गुफ़रानमाब, जहां स्वयं मौलाना कल्बे जव्वाद मुतवल्ली हैं, समेत कई जगहों पर कब्रों की खुलेआम बिक्री हो रही है, जो वक़्फ़ कानूनों का गंभीर उल्लंघन है। HTF ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन पूरे प्रदेश में आंदोलन तेज करेगा और शिया समुदाय की एक-एक वक़्फ़ संपत्ति को बचाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

जनता दर्शन : हर नागरिक की सेवा, सुरक्षा को प्रतिबद्ध है सरकार :मुख्यमंत्री

लोकतंत्र की शान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासकीय दायित्वों की व्यस्तताओं के बीच भी सोमवार को 'जनता दर्शन' किया। उन्होंने यहां आए प्रत्येक नागरिक से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। हापुड़ से आए दो सैनिकों ने मुख्यमंत्री से जमीन पर कब्जे की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को तत्काल मामले की जांच कर उचित निस्तारण का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 25 करोड़ प्रदेशवासियों की सेवा व सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने बच्चों को सीख दी कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और मोबाइल से दूर रहो।

सैनिकों ने की जमीन पर कब्जे की शिकायत -हापुड़ से आए दो सैनिक भी 'जनता दर्शन' में पहुंचे। एक सैनिक ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की। बताया कि वह और उनके भाई सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। उनके पिता नेत्रहीन हैं। उनकी जमीन ताऊ के लड़कों ने कब्जा कर ली है, जिनकी आपराधिक छवि है। ताऊ के लड़के हथियार के बल पर धमकी भी देते हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका प्रार्थना पत्र लेते हुए हापुड़ प्रशासन को निर्देश

दिया कि पूरे मामले की तत्काल जांच कराएं और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।

आप एस्टिमेट दीजिए, सरकार इलाज कराएगी -मुख्यमंत्री के समक्ष कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग लेकर भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि आप हॉस्पिटल से एस्टिमेट बनवाकर दें, सरकार इलाज में हरसंभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि आप मरीज के स्वास्थ्य की चिंता कीजिए, इलाज की चिंता सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त बिजली, नगर निगम, राजस्व आदि से जुड़े मामले भी आए, जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उचित निस्तारण का निर्देश दिया।

उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26: औद्योगिक क्षेत्र बना प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार

लोकतंत्र की शान

लखनऊ। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा विधानमंडल में प्रस्तुत पहली आर्थिक समीक्षा के अनुसार उत्तर प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र बीते वर्षों में अभूतपूर्व विस्तार के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनकर उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत लगभग 4,000 करोड़ की इंसेंटिव राशि का भुगतान किया गया, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। औद्योगिक गलियारों, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और आधुनिक अवसंरचना परियोजनाओं ने प्रदेश को उद्योगों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाया है।

दोगुने से ज्यादा बढ़ी कारखानों की संख्या-आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि कारखाना अधिनियम, 1948

के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों की संख्या में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 में जहां प्रदेश में 14,169 कारखाने पंजीकृत थे, वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 के नवंबर माह तक यह संख्या बढ़कर 30,695 तक पहुंच गई है। इसे प्रदेश की औद्योगिक प्रगति, निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा संकेत माना गया है। इसके साथ ही वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट में राज्य के उद्योगों के सकल मूल्य वर्धन में गत वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश के प्रमुख राज्यों में प्रथम स्थान पर है और अखिल भारतीय औसत वृद्धि दर (11.9 प्रतिशत) से दोगुनी से भी अधिक है।

निर्यात में भी दोगुने से अधिक वृद्धि-निर्यात के मोर्चे पर भी उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2016-17 में जहां प्रदेश से कुल 0.84 लाख करोड़ का निर्यात हुआ था, वहीं वर्ष 2024–25 में यह दोगुने से भी अधिक बढ़कर 1.86 लाख करोड़ तक पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक 1.31 लाख करोड़ का निर्यात किया जा चुका है। यह वृद्धि प्रदेश की विनिर्माण क्षमता, नीति आधारित विकास और वैश्विक बाजारों में उत्तर प्रदेश की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाती है। भारत सरकार द्वारा जनवरी 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में उत्तर प्रदेश ने चौथा स्थान प्राप्त किया है, जबकि वर्ष 2022 में प्रदेश सातवें स्थान पर था। लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा, जिसे निर्यात अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स सुधार और नीतिगत मजबूती का परिणाम माना गया है।

एसडीएम के नेतृत्व में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, भारी पुलिस बल रहा मौजूद

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः सोमवार को हसनपुर नगर क्षेत्र में एसडीम हिमांशु उपाध्याय के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, बताते चले कि हसनपुर नगर में संभल अड्डे से लेकर रहरा अड्डा तथा गजरौला अड्डा पर जगह-जगह दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है। जिसके चलते ट्रैफिक संचालन तथा अन्य गुजरने वाले वाहनों तथा यात्रियों व पैदल चलने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है वही आगामी शिवरात्रि पर इसी रोड से भारी संख्या में शिव भक्त गुजरेंगे। शिव भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े इसको लेकर प्रशासन सतर्क है। इसी को लेकर एसडीएम हिमांशु उपाध्याय, अधिशासी

अधिकारी विजयपाल सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज कुमार त्यागी, प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह के नेतृत्व में नगर पालिका कर्मियों ने अतिक्रमण अभियान के अंतर्गत सड़क पर अतिक्रमण करके रखे गए सामान को जप्त कर नगर पालिका की गाड़ियों में डाल लिया, जिसको लेकर पालिका कर्मियों अधिकारियों की दुकानदारों से नोक झोंक भी हुई, आपको बता दे कि नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। बीते दो दिन से शहर में अलाउंस कराकर दुकानदारों से अतिक्रमण को हटाए जाने की अपील की गई थी। उप-जिलाधिकारी हिमांशु उपाध्याय के नेतृत्व में नगर पालिका टीम ने जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटवाया। यह अभियान संभल अड्डा, रहरा अड्डा पर चलाया गया। इसके अलावा दुकानों के आगे से अवैध रूप से बनाए गए स्लैब, लोहे के जिले, टीन शेड, हटवाए गए। साथ ही सड़क किनारे फुटपाथ भी खाली करवाए गए। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान दुकानदारों तथा फुटपाथ पर ठेला लगाने वाले लोगों में हड़कंप मचा रहा। एसडीएम हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि शासन के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। तथा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा एवं जो लोग अतिक्रमण करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सीओ पंकज कुमार त्यागी, नायब तहसीलदार मनोज कुमार, ईओ विजयपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक अमित कुमार,कस्बा इंचार्ज राम प्रकाश सिंह, दिनेश बाबू के अलावा नगरपालिका टीम तथा सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

स्वस्थ दिनचर्या हर नागरिक का अधिकारः मुख्यमंत्री

लोकतंत्र की शान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले विधान भवन में स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। यह शिविर विधानसभा व विधान परिषद के सदस्यों के लिए लगाया गया है। इसमें केजीएमयू के चिकित्सकों द्वारा

स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। शिविर के उद्घाटन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों व जनप्रतिनिधियों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा यह शिविर लगाया गया है। यह शिविर माननीय सदस्यों व अन्य लोगों की सुविधा के लिए भी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ दिनचर्या हर नागरिक का अधिकार होनी चाहिए। सरकार भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस पर काम कर रही है। सीएम ने सदस्यों को तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हर सदस्य को तनावमुक्त रहकर उन्मुक्त वातावरण में दिनचर्या रखनी चाहिए, इससे रोग आकर भी भाग जाएगा।

H S S पब्लिक स्कूल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम बच्चों को लाइव दिखाया गया

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर : सोमवार को नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय एच.एस. एस. पब्लिक स्कूल, हसनपुर में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, परीक्षा-प्रबंधन तथा सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने हेतु "परीक्षा पे चर्चा 2026" के द्वितीय संस्करण का लाइव प्रसारण विद्यालय परिसर में बड़े स्क्रीन के माध्यम से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की ।कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को परीक्षा के समय तनाव कम करने, समय प्रबंधन, नियमित अध्ययन, आत्मविश्वास बनाए रखने तथा लक्ष्य निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण

विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। लाइव प्रसारण में दिए गए संदेशों ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे परीक्षा को भय नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखें और स्वस्थ दिनचर्या अपनाकर सफलता की ओर बढ़ें । विद्यालय के प्रधानाचार्य अंकुर काशिव ने इस अवसर पर कहा कि "परीक्षा पे चर्चा जैसे टीवी कार्यक्रम विद्यार्थियों को परीक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करने और आत्मबल बढ़ाने में अत्यंत सहायक हैं । विद्यालय का उद्देश्य केवल परीक्षा में अंक दिलाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना भी है ।" कार्यक्रम के अंत में छात्र-छात्राओं ने परीक्षा सम्बंधित अपने-अपने अनुभव साझा किए तथा शिक्षकों ने उन्हें व्यवहारिक सुझाव दिए । विद्यालय परिवार ने इस प्रेरणादायक कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी सहभागियों का धन्यवाद व्यक्त किया ।

आदमपुर में बंदरों के हमले से गिरकर 70 वर्षीय महिला की मौत

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर /आदमपुरः सोमवार को आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव चकफेरी में बंदरों के झुंड के अचानक हमले में छत से गिरकर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, बताते चले कि गांव चकफेरी निवासी 70 वर्षीय चमेली देवी पत्नी बाबूराम सोमवार को दोपहर लगभग 2:00 बजे अपने भाई मुन्ना की छत पर बैठी थी इसी बीच अचानक बंदरों के झुंड ने महिला पर हमला कर दिया बंदरों के अचानक हुए हमले से महिला को संभालने का मौका नहीं मिला और 70 वर्षीय चमेली देवी छत से नीचे गिर गई जिस कारण चमेली देवी के सिर व शरीर में गंभीर चोटे

आई परिजनों द्वारा चमेली देवी को अस्पताल ले जाया गया इसी बीच रास्ते में चमेली देवी की मृत्यु हो गई, लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा बंदरो को पकड़वा ये जाने की व्यवस्था करनी चाहिए ग्रामीणों में भारी रोज व्याप्त है बता दे की मृत्यु का गांव चाकरी में अपने मायके में रहकर अपना जीवन यापन कर रही थी l

संक्षिप्त समाचार

तेजप्रताप ने जिसे जयचंद बताया, उसके साथ कोर्ट पहुंचे तेजस्वी, सुनील को तेजप्रताप ने दी चेतावनी

पटना। लैंड फॉर जॉब केस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोमवार को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ रमीज नेमत भी मौजूद रहे। तेजप्रताप ने रविवार को पहली बार पांचों जयचंदों के नाम लिए थे, इसमें रमीज का भी नाम है। इधर, तेज प्रताप यादव ने सोमवार को दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और RJD नेता और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनील सिंह ने राजद को खोखला कर दिया है। तेजप्रताप ने कहा, 'सुनील सिंह को यह बात समझ लेनी चाहिए कि वो कभी मेरे चेला हुआ करते थे। मेरे पीछे-पीछे घूमते थे।' तेजप्रताप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, 'सुनील सिंह अपनी वाणी पर संयम रखें, नहीं तो सुधार देंगे।' प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजप्रताप ने सुनील सिंह पर भी रोहिणी आचार्य का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा, 'ऐसे लोगों ने मेरे पिता लालू यादव को बर्बाद कर दिया और अब पार्टी में मेरे पिता की भी नहीं चलती।'

7 शहरों में घना कोहरा,लो विजिबिलिटी से दरभंगा में हादसा

पटना। बिहार के 5 जिलों में आज कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है। समस्तीपुर, गोपालगंज, सुपौल, बगहा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में सुबह-सुबह घना कोहरा देखने को मिल रहा है। यहां जीरो विजिबिलिटी है। लोगों को गाड़ी की लाइट चालू कर के चलना पड़ रहा है। वहीं दरभंगा के NH-527 B पर घना कोहरा है। लो विजिबिलिटी के कारण ट्रक और ई-रिक्शा में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। अगले कुछ दिनों तक बिहार में मौसम शुष्क रहेगा और धीरे-धीरे तापमान बढ़ने की संभावना है। प्रदेश में फिलहाल बारिश की संभावना कम है।। सुबह-शाम ठंड महसूस होगी। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहेगा। तापमान में 1-3 डिग्री तक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हाल के दिनों में राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिला था। कुछ स्थानों पर विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई थी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सर्दियों में कोहरा बनने की मुख्य वजह ठंडी हवा, नमी और हवा की रफ्तार कम होना है। जब रात में जमीन ठंडी हो जाती है और हवा में नमी ज्यादा होती है तो छोटे-छोटे पानी के कण जमा होकर कोहरे बनते हैं। बिहार जैसे गंगा मैदानी इलाकों में ये स्थिति ज्यादा बनती है, क्योंकि यहां नमी अधिक रहती है। हवा की गति कई बार धीमी हो जाती है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और पछुआ हवाओं का असर भी तापमान को नीचे लाता है, जिससे सुबह के समय कोहरा ज्यादा घना हो जाता है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि आसमान साफ रहने पर भी सुबह कोहरा बन सकता है, क्योंकि रात में जमीन तेजी से ठंडी होती है।

12 फरवरी को पटना की सफाई व्यवस्था रहेगी ठप, पटना नगर निगम के कर्मी जाएंगे हड़ताल पर

पटना। पटना की सफाई व्यवस्था 12 फरवरी को ठप रहेगी। पटना नगर निगम के कर्मी हड़ताल पर जाने वाले हैं। 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 श्रम कोड लागू किए जाने के विरोध में 12 फरवरी को केंद्रीय श्रमिक संगठनों के राष्ट्रीय हड़ताल बुलाया है। पटना निगम कर्मियों ने इस हड़ताल को नैतिक समर्थन देने का सर्वसम्मति से फैसला लिया है। काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराने का फैसला लिया गया है। पटना नगर निगम के कर्मी अदालतगंज से प्रदर्शन करते हुए डाकबंगला तक जाएंगे। पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि, 44 श्रम कोड जो मजदूर के पक्ष में बना हुआ था, उसे खत्म कर 4 श्रम कोड को मालिक के पक्ष में बनाया गया है। इसी के खिलाफ हम लोग हड़ताल करेंगे। यह लेबर कोड मालिक के पक्ष में और मजदूर विरोधी है। इसके लागू हो जाने के बाद मजदूर अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकता है।

11 फरवरी को निकाला जाएगा विरोध मार्च: इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए 11 फरवरी को विरोध मार्च निकाला जाएगा। रामवतार शास्त्री गोलंबर, राजेंद्र नगर से लोहिया पार्क, कंकड़बाग तक जुलूस निकलेगा। इसके साथ ही दैनिक मजदूरों के लिए समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर गठित कमेटी की नगर विकास विभाग में बैठक बुलाने की भी योजना की जा रही है। वहीं, आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा कर्मियों के शोषण, बायोमीट्रिक हाजिरी में गड़बड़ी कर वेतन कटौती और वाहनों की मरम्मत लागत चालकों से वसूले जाने को लेकर भी विरोध जताया जाएगा।

अनुपस्थित अधिकारियों पर होगी कार्रवाई-डीएम, हाजीपुर परिवहन कार्यालय में डीएम का औचक निरीक्षण

हाजीपुर। वैशाली। हाजीपुर जिला परिवहन कार्यालय में डीएम वर्षा सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक दलाल को पकड़ा गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। निरीक्षण के समय डीटीओ कार्यालय में मौजूद थे, जबकि एडीटीओ और एमवीआई अधिकारी समेत कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। डीएम ने बताया कि कार्यालय में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह निरीक्षण किया गया। शिकायतें थीं कि अनाधिकृत व्यक्ति जिला परिवहन कार्यालय में प्रवेश करते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस तथा आरसी से संबंधित मामलों में डील करते हैं। इसी क्रम में आज यह औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पकड़े गए दलाल के मोबाइल में सभी सबूत देखे गए, जिससे पता चला कि वह बाहर से लोगों के साथ किस प्रकार डील कर रहा था। सदर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची है और दलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में डीएम ने कहा कि जब जांच शुरू हुई, तब केवल डीटीओ ही उपस्थित थे। एडीटीओ और एमवीआई समेत कोई अन्य पदाधिकारी मौजूद नहीं था। जो भी पदाधिकारी और कर्मी अनुपस्थित पाए गए हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने यह भी बताया कि सभी के कार्य आवंटन और लंबित कार्यों की जांच की जा रही है। अधिकारियों से लंबित कार्यों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। जांच टीम अभी भी कार्यालय में मौजूद है और लगभग दो घंटे तक जांच जारी रहेगी, जिसके लिए कार्यालय का गेट बंद रखा गया है। गिरफ्तार व्यक्ति के मोबाइल में मिली अवैध बातचीत और पैसे के लेन-देन के प्रमाण के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में यह पाया जाता है कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर कार्यों में देरी की जा रही थी या वे इस मामले में संलिप्त थे, तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

थानाध्यक्ष ने रेस्टोरेंट संचालक को पीटा, जांच जारी

हाजीपुर। वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट संचालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि लालगंज थानाध्यक्ष मनमोहन कुमार ने देर रात रेस्टोरेंट संचालक रणजीत कुमार को पीटा। यह घटना बाईपास रोड स्थित वेलकम फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा में हुई, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। रेस्टोरेंट संचालक रणजीत कुमार ने बताया कि रविवार रात चार से पांच अज्ञात लोग उनके ढाबे पर आए और उधार मांगने लगे। उधार देने से इनकार करने पर उन लोगों ने रणजीत के साथ मारपीट की थी। इस घटना के बाद किसी ने लालगंज थानाध्यक्ष को फोन कर सूचना दी। थानाध्यक्ष लगभग आधे से एक घंटे बाद मौके पर पहुंचे। इसी बीच, किसी अन्य व्यक्ति ने लालगंज एसडीपीओ को भी घटना की जानकारी दे दी थी। मौके पर पहुंचते ही थानाध्यक्ष मनमोहन कुमार ने रणजीत कुमार को गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। उन्होंने रणजीत को फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी। थानाध्यक्ष ने रणजीत पर एसडीपीओ को फोन करवाने, अपराधियों को बैठाने और शराब पार्टी करवाने का आरोप भी लगाया। रणजीत कुमार ने थानाध्यक्ष से कहा कि होटल में सीसीटीवी कैमरा लगा है और वे फुटेज चेक कर सकते हैं। आरोप है कि सीसीटीवी चेक करने के बहाने थानाध्यक्ष मनमोहन कुमार ने रणजीत के साथ मारपीट शुरू कर दी और उन्हें तीन से चार थप्पड़ मारे। इस दौरान थानाध्यक्ष सादे कपड़ों में थे। होटल में मौजूद अन्य लोगों ने थानाध्यक्ष की इस कार्रवाई का विरोध किया। यह पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है।

'शिक्षा मंत्री-झूठा मंत्री', पोस्टर के साथ टीआरई-4 कैंडिडेट्स का प्रदर्शन

पटना में पुलिस से भिड़े अभ्यर्थी, बैरिकेडिंग कर रोका गया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी

एजेंसी, पटना

पटना में शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 को लेकर अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की शुरुआत पटना कॉलेज से हुई, जो करीब दो घंटे बाद जेपी गोलंबर पर आकर खत्म हुई। अभ्यर्थी हाथों में 'शिक्षा मंत्री झूठा है' और 'I LOVE TRE-4' लिखे पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी जेपी गोलंबर तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। बैरिकेडिंग के दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झूमाझटकी हुई। कई अभ्यर्थियों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जबकि कुछ छात्र बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। BPSC ने वर्ष 2026 तक आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है, लेकिन इसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 का कोई उल्लेख नहीं है। इसे लेकर अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर TRE-4 को टालना चाहती है। कैलेंडर से TRE-4 के गायब रहने से हजारों अभ्यर्थियों में गुस्सा और निराशा दोनों बढ़ गई है।

TRE-4 गायब, सरकार की नीयत पर सवाल: पिछले सोमवार को जारी BPSC के परीक्षा कैलेंडर में 70वीं, 71वीं और 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CCE), न्यायिक सेवा, APO, तकनीकी और प्रशासनिक पदों समेत 50 से अधिक भर्तियों की संभावित तिथियां दी गई हैं। इस कैलेंडर में विशेष शिक्षक, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जैसी भर्तियों का भी जिक्र है, लेकिन TRE-4 पूरी तरह नदारद है। इससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या सरकार शिक्षक भर्ती को जानबूझकर लटका रही है।

सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है-छात्र संगठन: अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार ने पहले एक लाख से अधिक शिक्षक पदों पर भर्ती का वादा किया था। बाद में यह संख्या घटाकर करीब 26 हजार कर दी गई। अब हालात ऐसे हैं कि सरकार उतनी वैकेंसी भी देने को तैयार नहीं दिख रही है। छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है और जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही।

शिक्षा मंत्री ने TRE-4 पर रखा था अपना पक्ष: शिक्षा मंत्री ने हाल ही में दैनिक भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में TRE-4 को लेकर स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने कहा था कि, 'बिहार देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां दो साल में 2.70 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। यह कोई निजी भर्ती नहीं, बल्कि पूरी तरह सरकारी प्रक्रिया है, जिसमें रोस्टर क्लियरेंस जरूरी होता है।' मंत्री के अनुसार, चुनाव की वजह से भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई। फिलहाल आधे जिलों से रोस्टर क्लियरेंस मिल चुका है, जबकि बाकी जिलों का इंतजार है। रोस्टर मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग आरक्षण नियमों के तहत प्रक्रिया पूरी करेगा।

25 हजार पदों पर भर्ती की उम्मीद: शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि इस बार करीब 25 हजार शिक्षक पदों पर भर्ती की संभावना है। किस विषय में कितनी जरूरत है, इसका आकलन किया जा रहा है। उन्होंने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया था कि जनवरी के बाद TRE-4 की प्रक्रिया शुरू होगी।

पटना, भागलपुर, औरंगाबाद सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी

एजेंसी, पटना

पटना, पटना सिटी, औरंगाबाद और भागलपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके साथ ही औरंगाबाद की दाउदनगर अनुमंडल कोर्ट को भी मेल भेजा गया है। सिविल कोर्ट पटना, भागलपुर, औरंगाबाद और जिला बार एसोसिएशन के नाम मेल पर लेटर भेजा गया है। इसमें लिखा है कि जज के चैंबर और वॉशरूम में 4RDX रखे हैं। रिमोट से ब्लास्ट करेंगे।

♦ लेटर में लिखा- जज के चैंबर और वॉशरूम में 4आरडीएक्स रखे हैं, रिमोट से ब्लास्ट करेंगे

धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। वकील और जज अपने चैंबर से बाहर निकल गए हैं। इसके साथ ही बिहार के सभी कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना के पीरबहोर थाने की पुलिस कोर्ट परिसर में छानबीन कर रही है। फिलहाल कोर्ट को बंद कर दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कैदी, गवाह सभी को लौटा दिया गया है।

पटना सिटी कोर्ट को भी उड़ाने की मिली धमकी: पटना सिटी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिसके बाद पूरे कोर्ट परिसर में अफरातफरी का माहौल देखा गया। इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी गई। सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाना की पुलिस बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड टीम कोर्ट पहुंची और चप्पे-चप्पे की छानबीन शुरू कर दी है। इसे लेकर एक अधिवक्ता ने कहा, 'बार-बार इस तरह की अफवाह से न्यायालय का कार्य बाधित होता है। इस तरह की अफवाह फैलाने वालों को प्रशासन को खोजना चाहिए और उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए।'

आलमगंज थाना प्रभारी राहुल कुमार ठाकुर ने बताया कि कोर्ट परिसर को सील करके बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड टीम के साथ जांच शुरू कर दी गई है।

पटना में अतिक्रमण हटाने के दौरान झड़प

एजेंसी, पटना

पटना के कंकड़बाग इलाके के मेदांता अस्पताल के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसक झड़प हुई है। इसमें पुलिस कर्मियों और स्थानीय लोगों को चोटें आईं हैं। शहर में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी के तहत आज मेदांता के पास से अवैध तरीके से रह रहे लोगों को हटाया जा रहा था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इसके बाद हो मौके पर हल्ला होने लगा। इस दौरान पुलिस टीम पर प्रदर्शन कारियों ने पथराव करना शुरू कर दिया। स्थानीय महिला ने बताया कि, 'नगर निगम के लोग आए उन्होंने पहले कहा कि अपनी झुग्गी झोपड़ी केवल नीचे गिरा दीजिये। हम लोगों ने गिरा दिया। इसके बावजूद हटाने लगे। तोड़ फोड़ शुरू कर दी गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं। झुग्गी के लोगों के विरोध को देखते हुए आस पास के थाने के भी पुलिस कर्मी पहुँच गए हैं। नगर दंडाधिकारी आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने आई थी। पुलिस बल भी था। इसी दौरान अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, और कुछ अन्य पदाधिकारियों को चोट लगी है।

♦ कंकड़बाग में पुलिसकर्मी-स्थानीय लोग भिड़े, दोनों तरफ के लोगों को आई चोटें

जेल में ही रहेंगे पप्पू यादव, बेल पर सुनवाई टली 31 साल पुराने केस में हुई है सांसद की गिरफ्तारी

एजेंसी, पटना

पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई टल गई है। फिलहाल वे पटना की बेऊर जेल में ही रहेंगे। मेल से पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद MP-MLA कोर्ट को भी खाली कराया गया है। इसी वजह से आज बेल पर सुनवाई नहीं हो पाएगी। फिलहाल वे पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। बेऊर ले जाने से पहले उनका पीएमसीएच में मेडिकल चेकअप हुआ था। अस्पताल के अधीक्षक राजीव कुमार के अनुसार वे फीट हैं, हालांकि बेऊर जाने के वक्त वे एंबुलेंस में लेटे हुए थे।

वहीं, दूसरी तरफ सांसद और NEET छात्रा के समर्थन में रविवार को पटना से दिल्ली तक प्रदर्शन होता रहा। पटना में कांग्रेस कार्यकार्ताओं ने 'पप्पू यादव को रिहा करो' के पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर तक जला दिए। वहीं, दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी सांसद पप्पू यादव के समर्थन और छात्रा को न्याय दिलाने को लेकर प्रदर्शन हुआ। इसमें पीड़िता की मां और परिजन भी शामिल हुए थे। इसके अलावा करीब सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे थे।

पप्पू यादव लगातार सरकार को घेर रहे थे: NEET छात्रा मामले को लेकर पप्पू यादव लगातार सरकार और प्रशासन को घेर रहे थे। उन्होंने अस्पताल से जुड़े कुछ लोगों के कथित ऑडियो क्लिप भी जारी किए थे, जिनमें इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए गए थे।

अब तक पप्पू यादव बिहार में इस मुद्दे पर आवाज बुलंद कर रहे थे। अब वे इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने लगे थे। सबसे पहले उन्होंने संसद में इस मामले पर प्रदर्शन किया। वे पोस्टर वैनर के साथ संसद के बाहर खड़े दिखे। जानकारी के मुताबिक, पप्पू यादव NEET छात्रा मामले में दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले थे। इससे पहले शुक्रवार देर रात उन्हें 31 साल पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया गया।

मलाही पकड़ी, खेमनीचक मेट्रो स्टेशन होली बाद होगा शुरू

♦ जांच के लिए दिल्ली से आ रही टीम, पटना जंक्शन के पास बन रहा इंटरचेंज स्टेशन

एजेंसी, पटना

पटना मेट्रो के दो नए स्टेशनों को शुरू करने की कवायद की जा रही है। मलाही पकड़ी और खेमनीचक मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा होली बाद शुरू होगी। दूसरी ओर पटना जंक्शन के पास स्टेशन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। यह स्टेशन पूरे मेट्रो नेटवर्क का सबसे बड़ा स्टेशन होगा। तीन तल वाला यह स्टेशन एक इंटरचेंज स्टेशन के रूप में काम करेगा। यहां से मेट्रो कॉरिडोर-वन और कॉरिडोर-टू के सभी स्टेशनों तक सीधी कनेक्टिविटी होगी।

फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयेंगे कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी: मलाही पकड़ी और खेमनीचक मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा शुरू करने से पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी की (CMRS) अंतिम जांच प्रस्तावित है। सभी तकनीकी और सुरक्षा मानकों पर खरे उतरने के बाद, मार्च के पहले सप्ताह में इन दोनों स्टेशनों से मेट्रो सेवा शुरू हो सकती है। मेट्रो अधिकारियों के अनुसार, CMRS की टीम 25 से 28 फरवरी के बीच पटना पहुंचेगी। इस दौरान टीम मलाही पकड़ी और खेमनीचक स्टेशन के ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम, प्लेटफॉर्म सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाएं और अन्य तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच करेगी। जंक्शन मेट्रो स्टेशन का निर्माण बुद्धा पार्क के पास हो रहा है। इसका प्लेटफार्म जंक्शन के पास बने पुल के नीचे तक फैला हुआ होगा। पहले तल पर टिकट काउंटर, जांच द्वार और अन्य यात्रियों की सुविधाएं होंगी। दूसरे और तीसरे तल पर अलग-अलग प्लेटफार्म बनाए जाएंगे, जहां तक पहुंचने के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट की व्यवस्था की जाएगी।

तेज प्रताप यादव पूरे बिहार में करेंगे पैदल मार्च, कहा- जयचंदों ने राजद को बर्बाद किया

एजेंसी, पटना

पटना में सोमवार को तेजप्रताप यादव ने अपने संगठन के साथ बैठक की। इस दौरान जेजेडी के विस्तार को लेकर चर्चा भी हुई। बैठक के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो बिहार में पैदल यात्रा पर निकलने वाले है। बिहार के 38 जिलों में उनकी यह पैदल यात्रा निकलेगी।वहां के लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। तेज प्रताप ने सुनील सिंह पर हमला बोला। कहा कि RJD के लोगों का आपने कई बार अपमान किया है। राजद का क्या मामला है, नहीं है मुझे नहीं पता। इसलिए RJD 25 सीटों पर आ गई है। RJD में जो जयचंद हैं, उन्होंने मेरे पिता लालू यादव को बर्बाद कर दिए। अब मेरे पिता की RJD में कुछ नहीं चलती है। जयचंदों की वजह से राजद 25 पर आ गई, अब जीरो पर आएगी।

MLC सुनील सिंह पर तेज प्रताप यादव ने कहा, हम उनको बता देते हैं कि हमारे जो मामा थे, वह उनके चेला रह चुके हैं। उनके पीछे-पीछे घुमा करते थे। सुनील सिंह ने तो RJD को खोखला कर दिया। अपनी वाणी पर संयम नहीं रखेगा तो खुद भी जल्द खोखला हो जाएगा। सुनील सिंह ने मुझे बच्चा कहा...बचा कब चाचा निकल जाएगा कोई नहीं जनता है। सुनील सिंह अपनी वाणी पर संयम रखिए नहीं तो आपको सुधार दिया जाएगा।

कहा- लालू यादव की असली पार्टी है JJD: RJD के लोग तो हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं, जो चूड़ा दही का हमने भोज रखा था। हमारे पिता लालू यादव ने हमें जाकर आशीर्वाद दे दिया। अब सबको पता चल गया कि लालू यादव की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल ही है। राजद के कई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था चुनाव के समय की पैसे लेकर टिकट दिया गया। इस पर तेज प्रताप ने कहा कि यह तो सच्चाई है। हमने तो इसे करीब से देखा है, जब हम वहां रहते थे क्या क्या होता था।

MLC चुनाव में सभी सीटों पर उतारेंगे कैंडिडेट: वहीं, JJD के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और खुला अधिवेशन की बैठक 16 अप्रैल को होगी। उन्होंने कहा 16 अप्रैल शुभ दिन है उसे दिन हमारे नेता का जन्मदिन भी है। इस बैठक में पार्टी के आगे के रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। एमएलसी चुनाव में भी हमारी पार्टी सभी सीटों पर कैंडिडेट उतरेगी। बता दें कि तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अनुष्का यादव ने एक बच्ची को जन्म दिया है, इसकी चर्चा रविवार से लगातार हो रही है। रविवार को ही केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने ट्वीट कर तेजप्रताप और अनुष्का को बधाई भी दी थी। हालांकि इसके बाद ट्वीट हटा लिया था।

'जोड़ी मोदी-नीतीश के...'गाने से नितिन नवीन का वेलकम, बापू सभागार में लहराया भगवा गमछा

एजेंसी, पटना

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन सोमवार को पहली बार पटना पहुंचे। ढोल-नगाड़ों के साथ बीजेपी दफ्तर में उनका स्वागत किया गया। वे विधानमंडल दल की बैठक करेंगे। बीजेपी कार्यालय में मीडिया की एंट्री नहीं दी गई है। पटना एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जोड़ी 'नीतीश-मोदी के हिट हो गइल' गाने के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में बाइक रैली निकाली गई। एयरपोर्ट से नितिन नवीन सीधे बापू सभागार पहुंचे, जहां भाजपा की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। यहां भगवा गमछा लहरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं ने नए अध्यक्ष का स्वागत किया। इस समारोह में बिहार के सभी जिलों से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और संगठन को और अधिक मजबूत करने का संदेश दिया।

संबोधन के दौरान भावुक हुए नितिन नवीन: अपने संबोधन के दौरान नितिन नवीन भावुक हो गए। उन्होंने इस मौके को अपने लिए भावुक क्षण बताया और पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, "2006 में पिता के निधन के बाद मैंने राजनीति में कदम रखा। उस समय पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया और वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मुझे आगे बढ़ने का अवसर दिया।" उन्होंने कहा कि कई विधायक और कार्यकर्ता ऐसे रहे हैं, जिन्होंने उंगली पकड़कर उन्हें राजनीति में चलना सिखाया। ये सभी लोग आज भी उनके स्मरण में हैं और उनकी राजनीतिक यात्रा का अहम हिस्सा रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए नितिन नवीन ने कहा कि जिस विश्वास के साथ उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करेंगे। उन्होंने कहा, "मेरी राजनीतिक शुरुआत बिहार में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हुई थी और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के बाद भी मैं खुद को कार्यकर्ता ही मानता हूं।" बीजेपी अध्यक्ष ने उन कार्यकर्ताओं को नमन किया, जिन्होंने कभी उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा, लेकिन आज उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं।

♦ बीजेपी दफ्तर में विधानमंडल दल की बैठक करेंगे

नितिन नवीन का पार्टी अध्यक्ष बनना बिहार के लिए सम्मान की बात-संजय सरावगी: प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि, 'राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बिहार दौरा हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का पल है। 45 साल की उम्र में नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पूरे बिहार के लिए सम्मान की बात है।' अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान नितिन नवीन कई संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नागरिक अभिनंदन समारोह के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी के साथ एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक करेंगे।

मंगलवार को नितिन नवीन जाएंगे विधानसभा: 10 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार विधानसभा जाएंगे, जहां विधायक और विधानपार्षद उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद वे दोपहर में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। दौरे के अंतिम दिन 10 फरवरी की शाम वे पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनके स्वागत और कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए बिहार भाजपा पूरी तरह तैयारियों में जुटी हुई है।

संक्षिप्त समाचार

सांझा साहित्य मंच की मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन

लोकतंत्र की शान : राजेंद्र करनाल की रिपोर्ट: सांझा साहित्य मंच की मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन सेक्टर 12 स्थित हुडा कार्यालय में किया गया।गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में डा. कमर रईस जी पहुँचे। विशिष्ट अतिथि दलीप खरैरा रहे।अध्यक्षता मैडम गुरविंद्र कौर ने की।मंच संचालन सतविंद्र राणा ने किया। कृष्ण कुमार निर्माण ने भाईचारे का संदेश देते हुए कहा कि---कोए गैर नहीं सै जग म्हं,सभ अपणै सै,यार यो मैं-मेरी का चस्मा हटाक्यै देख। दिल नै दिल तै यार मिलाक्यै देख,आपणी बी किस्मत ने आजमाक्यै देख।

अशोक मलंग बोले कि- लाठी का जोर चलता,करती है राज लाठी,उसकी ही भैंस समझो,जिसकी है लाठी। धर्मेंद्र अरोड़ा मुसाफिर ने फरमाया कि --- छिपाया बहुत हाल दिल का मगर,गजल जब कही आईना हो गया। दलीप खरैरा ने कहा कि--उलझना भी जरूरी है,सुलझने के लिए,डगमगाना भी जरूरी है,संभलने के लिए।

गुरविंद्र कौर गुरी ने कहा कि : मेरी बेटी मेरा अभिमान,पर तेरी बेटी से मुझे क्या काम। जय भारद्वाज तरावड़ी ने फरमाया कि--है जायज सब मुहब्बत में सुलह भी और लड़ाई भी,उसे दिल से कहो अपना,तुम्हारा हो भी सकता है। गुरमुख सिंह वड़ैच बोले कि --कुछ नशा तो आपकी बात का है,कुछ नशा हसीं जज्बात का है,हमें आप यूं ही दिवाना न कहिए,ये नशा तो आज की मुलाकात का है। सुरेंद्र कल्याण बुटाना बोले कि---जाणै आलै थौड़ा रूक जाईय रै। सतविंद्र राणा ने फरमाया कि--वो कि जिसने तिनका भी समझा है पर्बत की तरह, जिंदगी क्या,और क्या है जीना क्या समझ वो पाएगा।

यमुनानगर में कपड़ा शोरूम पर फायरिंग, दहशत फैलाने की कोशिश

लोकतंत्र की शान : यमुनानगर। जिले के छछरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव कोट मुस्तरका में रविवार रात एक कपड़ों के शोरूम के बाहर हथियार से गोली चलाए जाने की गंभीर घटना सामने आई है। इस वारदात से इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार घटना रविवार रात की है, जब शोरूम मालिक अपने प्रतिष्ठान के बाहर मौजूद था। इसी दौरान वहां पहले से खड़े कुछ युवक आपस में ऊंची आवाज में बहस कर रहे थे। जब शोरूम मालिक ने उन्हें हंगामा न करने को कहा, तो बात अचानक बिगड़ गई। आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने हथियार निकालकर अपने साथी को सौंप दिया, जिसके बाद शोरूम की ओर एक राउंड फायर कर दिया गया। गोली चलने की आवाज से मौके पर मौजूद लोग घबरा गए। शोरूम मालिक ने तत्काल अंदर जाकर अपनी जान बचाई। इसके बाद आरोपी युवक शोरूम के भीतर घुस आए और वहां कार्यरत एक कर्मचारी को डराने-धमकाने लगे। आरोपियों ने हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि फायरिंग का उद्देश्य दहशत फैलाना था। छछरौली थाना पुलिस ने शोरूम मालिक की शिकायत के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी के अनुसार, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि घटना की कड़ियों को जोड़ा जा सके।

फरीदाबाद जेल में आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या

लोकतंत्र की शान : फरीदाबाद। फरीदाबाद की जेल में रविवार देर रात कैदियों के बीच हुई मारपीट के दौरान आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई। मृतक आतंकी को कुछ समय पहले ही जम्मू-कश्मीर से फरीदाबाद जेल में शिफ्ट किया गया था। हत्या का आरोप इसी जेल में बंद अरूण चौधरी नामक कैदी पर लगा है।घटना के बाद सभी कैदियों को बैरकों में बंद कर दिया गया है। आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या की खबर जेल प्रबंधन को सोमवार की सुबह गिनती के दौरान मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। फरीदाबाद पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आंतकी अब्दुल रहमान को गुजरात एटीएस की मदद से आईबी ने 2 मार्च 2025 को दो हैंड ग्रेनेड के साथ पाली गांव के पास पकड़ा था। उसने अयोध्या को दहलाने की साजिश रची थी। अब्दुल रहमान अलकायदा इन इंडियन सब-कांटिनेंट (एक्यूआईएस) के कुख्यात आतंकी अबू सूफियान के संपर्क में था। अब्दुल रहमान यूपी के मिल्कीपुर का रहने वाला था। उसके पास कुछ विडियो भी मिले थे, जिनमें राम मंदिर से जुड़ी कुछ डिटेल थी। जांच पता चला था कि करीब डेढ़ साल से अब्दुल रहमान सोशल मीडिया अकाउंट पर भड़काऊ वीडियो अपलोड करता था। पुलिस प्रशासन अभी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहा है। पुलिस तथा जेल विभाग के आला अधिकारियों ने जेल में पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

अल्ट्राटेक सीधी सीमेंट में श्रम संहिताओं की कार्यशाला आयोजित

कुल वेतन का आधा होगा अब मूल वेतन

लोकतंत्र की शान

सीधी। अल्ट्राटेक सीधी सीमेंट प्लांट में बीते 9, फरवरी को भारत सरकार द्वारा लागू किए गए केन्द्रीय श्रम कानूनों की चार श्रम संहिताओं के संबंध की कार्यशाला का अयोजन यूनिट प्रमुख बीपी सग्गू जी के दिशा-निर्देशन में केन्द्रीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी सतना के अग्नि मित्र बाजपेई के समक्ष प्लांट के एचआर, प्रमुख अभिषेक शर्मा जी के मार्गदर्शन में/ईआर एवं प्रशासनिक प्रमुख दिनेश शर्मा की सुव्यवस्था में किया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बताया गया कि औद्योगिक जगत में श्रमिकों के कार्य करने की स्थिति में सुधार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नियमों के सरलीकरण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 29, पुराने केन्द्रीय श्रम कानूनों का युक्तिकरण प्रमुख तया न्यू श्रम कोड की चार संहिताओं को प्रभावी कर श्रमिकों, नियोक्ताओं तथा ट्रेड यूनियनों के संबंधों को मजबूत किया गया है। जिसमें वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य,काम करने की स्थिति संहिता समावेशित है। उन्होंने बताया कि सैलरी संरचना में कुल वेतन का 50%,मूल वेतन निर्धारित किया गया है,। पूर्व में रहे पांच साल के स्थान पर एक साल की नौकरी पर ग्रेजुटी,45, वर्ष के ऊपर मुफ्त में वार्षिक मेडिकल सुविधा, ओवर टाइम की ड्यूटी पर दुगुना भुगतान, सप्ताह में 48, घंटे के कार्य का विकल्प,आदि के प्रावधान बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक श्रमिक को नियुक्ति पत्र दिया जाना, अनिवार्य किया गया है।उपस्थिति श्रमिकों, श्रमिक संगठनों, संविदाकारों को अवगत कराते हुए कहा गया कि विषम परिस्थितियों में औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए श्रम अदालतें हैं, जहां मध्यस्थता की समुचित व्यवस्था है। ईआर विभाग प्रबंधक शांति मया दास के संयोजकत्व में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध ट्रेड यूनियन व सीटू यूनियन की प्रबंध कार्यकारिणी तथा संविदाकारों का सम्मिलन समुचित संख्या में रहा।

बैडमिंटन इण्डोर हॉल माधव नगर में वुडन फ्लोरिंग कार्य का पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा बैडमिंटन इण्डोर हॉल, माधव नगर, जिला कटनी में चल रहे बैडमिंटन वुडन फ्लोरिंग के नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी तथा संबंधित विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में लगे वुडन फ्लोर को हटाकर उसके नवीनीकरण एवं सुधार/मरम्मत का कार्य मेसर्स अमेज स्पोर्ट्स, 214 अम्बेडकर नगर, तहसील हुजूर, भोपाल (म.प्र.) के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित एजेंसी के पदाधिकारी को समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा कुश्ती खिलाड़ियों के अभ्यास हेतु नगर निगम आयुक्त कटनी से कावसजी वार्ड में स्थित नवनिर्मित अखाड़ा हॉल में कुश्ती अभ्यास की व्यवस्था किए जाने संबंधी पत्राचार करने हेतु निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त खेलों इंडिया एथलेटिक्स प्रशिक्षक श्रीमती रेखा द्वारा ऑर्डिनेंस ग्राउंड में अभ्यास के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा ऑर्डिनेंस ग्राउंड के संबंधित पदाधिकारियों से नियमित अभ्यास के संबंध में पत्राचार किए जाने हेतु जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया।

नगर निगम कार्यालय एवं जोन कार्यालय माधवनगर में जनसुनवाई का आयोजन मंगलवार को

» महापौर श्रीमती सूरी निगम कार्यालय एवं निगमायुक्त सुश्री परिहार जोन कार्यालय माधवनगर में नागरिकों के आवेदनों पर करेंगी सुनवाई

लोकतंत्र कि शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी : नगर निगम से संबंधित आम नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण कर शासन मंशानुरूप समयबद्ध तरीके से शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ आम जन तक सरलता से पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार 10 फरवरी को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक नगर निगम कटनी कार्यालय के साथ ही जोन कार्यालय माधवनगर में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने निगम कार्यालय तथा जोन कार्यालय में मंगलवार को आयोजित होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान निगम के अधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश निर्देश दिए है। नगर निगम कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान पहुंचने वाले आवेदकों के आवेदनों पर महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी द्वारा सुनवाई की जाकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये जाएगें। वहीं जोन कार्यालय माधवनगर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार द्वारा नागरिकों के आवेदनों पर सुनवाई की जाकर क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। नगर निगम कार्यालय तथा जोन कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान नागरिक गण साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, पेंशन, अतिक्रमण सहित नगर निगम की विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं से संबंधित शिकायत, समस्या अथवा सुझाव संबंधी आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। उल्लेखनीय है कि महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी एवं निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार द्वारा आम नागरिकों और निगम प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ निश्चित समयावधि में करनें हेतु प्रत्येक मंगलवार निगम कार्यालय तथा जोन कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

किसान ने पटवारी से सौदा करने से किया इंकार तो बदल दिए रिकार्ड से नाम

» पीड़ित किसान ने सुनाई मीडिया को अपनी व्यथा
» मामला गोपदबनास तहसील के सीधी खुर्द का

लोकतंत्र की शान

सीधी। शहर के कुछ हल्का पटवारी अपने कारनामों को लेकर आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं, जिसके चलते समूचे राजस्व विभाग की छवि धूमिल हो रही है। जिसका जीता जागता उदाहरण गोपद बनास तहसील के सीधी खुर्द ग्राम का सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित किसान राममिलन कुशवाहा ने बताया कि हल्का पटवारी जनार्दन मिश्रा द्वारा भूमाफिया अरुण कुमार गुप्ता निवासी वार्ड क्रमांक 21 से साठगांठ कर पूर्व में तय राशि अनुसार निष्पादित विक्रय पत्र अनुसार राशि 01 करोड़ 60 लाख रुपए न देने से मना कर दिया गया और मेरे ऊपर पटवारी द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि उक्त भूमि अरुण कुमार गुप्ता को 01 करोड़ रुपए बिक्री कर दो, मेरे द्वारा मना कर दिया गया तो तो हल्का पटवारी जनार्दन मिश्रा ने मेरे खसरे में राममिलन कुशवाहा की जगह रामललन कुशवाहा दर्ज कर दिया गया है। पीड़ित किसान राममिलन कुशवाहा ने इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से दर्ज कराई है। बता दें कि हल्का पटवारी जनार्दन मिश्रा का यह कोई पहला मामला नहीं है इसके पूर्व भी इनके क्षेत्र के किसानों ने पटवारी की प्रताड़ना का आरोप लगा चुके है।

प्रापर्टी डीलर बना पटवारी

किसान राममिलन कुशवाहा ने बताया कि पटवारी जनार्दन मिश्रा एवं प्रापर्टी डीलर अरुण कुमार गुप्ता पार्टनर हैं, और दोनों के द्वारा मिलकर किसानों की औने पौने दाम पर जमीन क्रय कर मंहगे दामों में प्लाटिंग के बेची जा रही है। किसान राममिलन कुशवाहा ने बताया कि पटवारी जनार्दन मिश्रा द्वारा जानबूझकर मेरे नाम के साथ छेड़छाड़ किया गया है जिससे मैं अपनी भूमि अन्य किसी व्यक्ति को बिक्री न कर सकूं। पीड़ित किसान राममिलन कुशवाहा ने मीडिया के माध्यम से कलेक्टर एवं तहसीलदार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दोषी पटवारी जनार्दन मिश्रा के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग उठाई है, एवं खसरे को सुधार कराते हुए रामलालन कुशवाहा की जगह सही नाम राममिलन कुशवाहा की जाय।

जनपद सीईओ की लापरवाही से सेवा निवृत्त सचिव की डीएससी से हुआ लाखों का वारा-न्यारा

मामला सीधी जनपद के ग्राम पंचायत सरेठी का

लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के जनपद पंचायत सीधी अंतर्गत ग्राम पंचायत सरेठी में रिटायर्ड कर्मचारी की डीएससी से लाखों रुपए आहरित करने का मामला सामने आया है, अब रिटायर्ड कर्मचारी अपने सेवानिवृत्त होने के बाद राशि निकाले जाने का प्रमाण देते घूम रहा है। गौरतलब हो कि सीधी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सरेठी में बतौर सचिव पदस्थ रही श्रीमती मनोज सिंह 30 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गई, उनके सेवानिवृत्त उपरान्त जिला पंचायत सीईओ शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने उक्त पंचायत का सचिवीय प्रभार ग्राम पंचायत मौहरियाकला के सचिव भूपेन्द्र साकेत को अतिरिक्त प्रभार सौंपा था, जिनके द्वारा पूर्व सचिव की डीएससी से करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा की राशि आहरित कर ली गई है। इस पूरे गोलमाल में ग्राम पंचायत सरेठी के सरपंच की भूमिका अहम है, बताया जा रहा है कि रिटायर्ड सचिव श्रीमती मनोज सिंह के नाम जारी डीएससी से नवनियुक्त सचिव के साथ मिलकर सरपंच ने सरकारी खजाने में सेंध लगाने के लिए यह पूरा फर्जीवाड़ा किया है। बता दें कि यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला है, अगर इस पूरे मामले की जांच ईमानदारी पूर्वक कराई गई तो फर्जीवाड़े की कहानी में शामिल सभी चेहरे बेनकाब हो जाएंगे।

जनपद सीईओ की हैं लापरवाही

ग्राम पंचायतों में पदस्थ सचिवों की डीएससी बंद एवं चालू करने का अधिकार जनपद पंचायत सीईओ के पास होता है, जिनके द्वारा संबंधित बैंक एवं ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव को नई डीएससी चालू करने की सूचना जारी की जाती हैं, लेकिन सीधी जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा वित्तीय मामले को भी गंभीरता से नहीं लिया और इसी का फायदा उठाते हुए सरपंच एवं सचिव ने रिटायर्ड सचिव के डीएससी से लाखों रुपए आहरित कर लिए। जबकि जनपद सीईओ द्वारा अगर रिटायर्ड सचिव श्रीमती मनोज सिंह की डीएससी तत्काल बंद कर दी गई होती तो इस तरह बातें निकल कर सामने नहीं आती।

इधर भी घूम रही शक की सुई

बता दें कि ग्राम पंचायत सरेठी की सचिव श्रीमती मनोज सिंह 30 जनवरी को सेवानिवृत्त हुई है और जिला पंचायत से उनके सेवानिवृत्त होने के एक दिन पूर्व ही मोहरियाकला के सचिव भूपेन्द्र साकेत को अतिरिक्त प्रभार देने का आदेश जारी कर दिया गया। आमतौर पर यह देखा जाता था कि सेवानिवृत्त एवं स्थानांतरित कर्मचारी के मुक्त होने की दशा पर रिक्त होने की स्थिति को देखते हुए तथा मांग अनुसार नवीन कर्मचारी की पदस्थापना का आदेश जारी किया जाता था, लेकिन सरेठी पंचायत सचिव श्रीमती मनोज सिंह के सेवानिवृत्त होने के पूर्व ही मोहरियाकला सचिव को अतिरिक्त प्रभार सौंपने का आदेश जारी कर दिया गया। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे मामले में जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के संबंधित शाखा लिपिको की भूमिका सवालों के घेरे में है।

अल्ट्राटेक वर्क्स मैहर के विकास पर हमला! CSR सड़क बनी राजनीति का अखाड़ा, सरपंच के विरोध पर ग्रामीणों का दो टूक-हम प्रबंधन के साथ खड़े हैं

लोकतंत्र की शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

अल्ट्राटेक वर्क्स मैहर सीमेंट ग्रामीण जनजीवन को सुगम और सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है। इसी क्रम में देवरी ग्राम पंचायत में CSR मद से सड़क निर्माण की पहल सामने आई, लेकिन विकास की इस राह में राजनीति का रोड़ा खड़ा करने की कोशिश शुरू हो गई। सरपंच के विरोधी सुर अब पत्रों के माध्यम से खुलकर सामने आ रहे हैं। सूत्रों की मानें तो ग्राम विकास के लिए सरकार से आई राशि से घटिया सड़क निर्माण कराने वाले सरपंच को उद्योग प्रबंधन ने जिम्मेदारी नहीं सौंपी, जिससे बौखलाहट में विरोध की आग भड़काई जा रही है। हालांकि, स्थानीय ग्रामीणों ने साफ और आक्रामक शब्दों में मोर्चा संभाल लिया है। ग्रामीणों का कहना है—सरपंच चाहे जितना विरोध करे, सड़क बनेगी। हम अल्ट्राटेक उद्योग प्रबंधन के साथ हैं। ग्रामीणों ने प्रबंधन को बिना भय कार्य प्रारंभ करने का खुला समर्थन दिया है और चेतावनी दी है कि विकास में जो भी रोड़ा बनेगा, उससे वे खुद निपटेंगे। अब देवरी में संदेश साफ है—विकास रुकेगा नहीं, विरोध टिकेगा नहीं!

अमिलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा के नाम पर वसूली

» गरीब मरीजों से खुलेआम की जाती हैं रिश्वत मांग

लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमिलिया से एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम हीरादेही निवासी लाल बहादुर साकेत ने आरोप लगाया है कि अमिलिया स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स विद्या तिवारी द्वारा मरीजों और उनके परिजनों से खुलेआम पैसे की मांग की जाती है। पीड़ित लाल बहादुर साकेत अपनी बेटी के इलाज और प्रसव के लिए अमिलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचे थे, जहां उनसे कथित रूप से 500 की अवैध वसूली की गई। पीड़ित का कहना है कि वे अत्यंत गरीब परिवार से आते हैं। शासन की ओर से मिले कोटे का गेहूं बेचकर उन्होंने नर्स को 500 घूस के रूप में दिए, ताकि अस्पताल में डिलीवरी करवाई जा सके। इसके अलावा, नर्स द्वारा यह भी कहा गया कि अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं और सारी दवाइयां बाहर की मेडिकल दुकान से ही मंगवानी होंगी। पीड़ित के अनुसार नर्स ने साफ शब्दों में धमकी दी कि यदि दवाइयां बाहर से नहीं लाई गईं और पैसे नहीं दिए गए तो मरीज को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया जाएगा। यह कोई पहला मामला नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस तरह की शिकायतें पहले भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से की जा चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस पूरे मामले में उच्च अधिकारियों की मौन सहमति है, या फिर शिकायतों को जानबूझकर दबाया जा रहा है।

सरकार के दावों की खुल रही पोल

एक ओर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव, मुफ्त इलाज और दवाइयों के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर अमिलिया जैसे स्वास्थ्य केंद्रों में गरीब मरीजों से वसूली कर उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार से आम जनता का भरोसा सरकारी व्यवस्था से उठता जा रहा है। ग्रामीणों और पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, अमिलिया अस्पताल के प्रबंधन और संबंधित नर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी गरीब मरीज को इलाज के नाम पर अपमान और लूट का शिकार न होना पड़े।

पीड़ितों को राहत पहुंचाने कलेक्टर की अनोखी पहल

» गरीब शिकायत कर्ता को घर तक पहुंचने का मिलेगा टोकन

लोकतंत्र की शान

सीधी। अपनी पीड़ा सुनाने जिला मुख्यालय आने वाले पीड़ित गरीब जन को घर वापस जाने का इंतजाम जिला प्रशासन ने करने का निर्णय लिया है जिसके लिए जिला मुख्यालय से चलने वाली बसों के संचालकों और परिवहन अधिकारी की बैठक लेकर निर्णय लिया गया है। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी की अध्यक्षता में जिले के बस संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जनसुनवाई में दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से आने वाले गरीब एवं जरूरतमंद आवेदकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष "सुगम" व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर ने बताया कि जिला मुख्यालय में प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में जिले के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आवेदक अपनी समस्याओं के समाधान हेतु पहुंचते हैं, जिनमें कई अति गरीब वर्ग के लोग भी शामिल होते हैं। ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा "सुगम टोकन" जारी करने की पहल की जा रही है। इस टोकन के आधार पर जनसुनवाई के पश्चात पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क घर तक पहुंचाने की व्यवस्था बस संचालकों के सहयोग से सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर की इस संवेदनशील पहल की सभी बस संचालकों ने सराहना करते हुए इसे सहर्ष स्वीकार किया तथा प्रशासन के साथ मिलकर जरूरतमंदों की सहायता करने का भरोसा दिलाया। कलेक्टर ने कहा कि इस सामाजिक पहल में उत्कृष्ट सहयोग प्रदान करने वाले बस संचालकों को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा।

सुरक्षित बस संचालन के निर्देश

बैठक के दौरान कलेक्टर ने बस संचालकों को सुरक्षित एवं जिम्मेदार बस संचालन के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी बसों में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को बैठाया जाए, वाहनों की नियमित फिटनेस एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, तेज गति एवं लापरवाही से वाहन संचालन से बचा जाए तथा यातायात नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, संयुक्त कलेक्टर राजेश शुक्ला, उपखंड अधिकारी गोपद बनास राकेश शुक्ला, उपखंड अधिकारी चुरहट शैलेश द्विवेदी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आशुतोष सिंह भदौरिया सहित जिले के समस्त बस संचालक उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बस संचालकों से प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर इस पहल को सफल बनाने की अपील की।

संक्षिप्त समाचार

विमान दुर्घटना के डेढ़ साल बाद सौर्य एयरलाइन्स को मिली उड़ान की अनुमति

काठमांडू। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई दुर्घटना के डेढ़ वर्ष बाद निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी सौर्य एयरलाइन्स को उड़ान संचालन की अनुमति मिल गई है। पोखरा के लिए 24 जुलाई, 2024 को उड़ान भरने के दौरान काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सौर्य एयरलाइन्स का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान ने रनवे 02 से उड़ान भरी थी और टेक ऑफ के कुछ ही सेकेंड के बाद पूर्व दिशा में रनवे 20 के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह विमान सी–चेक नामक विस्तृत तकनीकी निरीक्षण के लिए काठमांडू से पोखरा जा रहा था। दुर्घटनाग्रस्त विमान में सवार 19 लोगों में से कैप्टन मनीष शाक्य को छोड़कर 18 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने सौर्य एयरलाइन्स का एयरक्राफ्ट ऑपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया था। प्राधिकरण ने सोमवार को सौर्य एयरलाइन्स के एओसी का नवीनीकरण करते हुए पहले लगाया गया निलंबन भी हटा दिया। प्राधिकरण के सूचना अधिकारी ज्ञानेंद्र भुल के अनुसार यह नवीनीकरण जनवरी, 2027 तक मान्य रहेगा।

प्रचंड का दावा- नेपाल में सोशल मीडिया अल्गोरिदम का प्रयोग लोकतंत्र के लिए खतरा

काठमांडू। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल 'प्रचंड' ने कहा है कि सोशल मीडिया अल्गोरिदम से जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वह देश के चुनाव के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ है। सोमवार को काठमांडू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रचंड ने कहा कि विश्व साम्राज्यवाद विभिन्न देशों में भू-राजनीतिक हस्तक्षेप कराने के लिए सोशल मीडिया आधारित दिखावटी गतिविधियों (स्टंट्स) का उपयोग कर रहा है और नेपाल भी इस प्रभाव से अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि विचारधारा, राजनीतिक सिद्धांत, इतिहास या विरासत के बिना कुछ लोग केवल सोशल मीडिया के सहारे लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक बढ़ती हुई चुनौती है। प्रचंड ने इन प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए नए संकल्प और गंभीर राजनीतिक पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्र और जनता के प्रति समर्पित राजनीति को फिर से सशक्त रूप में आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने माना कि वर्तमान समय सोशल मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी से संचालित है, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जमीनी स्तर पर जनता से सीधा संवाद ही सबसे प्रभावी राजनीतिक तरीका बना हुआ है।

ढाई दशक में 26.32 लाख पर्यटक पहुंचे अन्नपूर्णा

काठमांडू। विश्व प्रसिद्ध पदयात्रा पर्यटन स्थल अन्नपूर्ण क्षेत्र में पिछले 25 वर्ष में कुल 26 लाख 32 हजार 34 विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं। अन्नपूर्णा चोटी उत्तर-मध्य नेपाल के गंडकी प्रांत में है। यह हिमालय की अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह 8,091 मीटर (26,545 फीट) की ऊंचाई के साथ दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत पुंजक पश्चिम में काली गंडकी तंगघाटी, उत्तर व पूर्व में मर्स्यांग्दी नदी और दक्षिण में पोखरा घाटी से घिरा है। यह आंकड़ा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना (एसीएपी) ने जारी किया है। एसीएपी के अनुसार, 2001 में 65,313 पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्र आए थे, जबकि 2025 में अब तक सबसे अधिक 2,99,831 पर्यटक आए । इस अवधि में सबसे कम 16,105 पर्यटक 2021 में आए। इसे कोविड-19 महामारी का प्रभाव माना गया। 2001 से 2010 तक हर साल एक लाख से कम पर्यटक आते रहे, लेकिन 2011 में नेपाल भ्रमण वर्ष के दौरान यह संख्या पहली बार एक लाख से ऊपर पहुंची। 2015 में भूकंप के बाद आगमन में कमी आई। इसके बाद धीरे-धीरे संख्या बढ़ी और 2022 से फिर वृद्धि हुई है। 2022 में 1,29,723, 2023 में 1,91,558 और 2024 में 2,44,039 पर्यटक आए। 2025 में यह संख्या सबसे अधिक और रिकॉर्ड तोड़ 2,99,831 रही। एसीएपी प्रमुख डा. रबिन कडरिया के अनुसार, 2025 में 177,628 दक्षिण एशियाई देशों और 122,203 अन्य देशों के पर्यटक पहुंचे। उन्होंने कहा कि पर्यटन में वृद्धि जारी है और ट्रैकिंग के शौकीनों से लेकर धार्मिक यात्रियों तक हर तरह के पर्यटक इस क्षेत्र में आ रहे हैं। अन्नपूर्ण चक्रीय मार्ग पर अन्नपूर्णा बेस कैंप, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, तिलिचो झील, थोरोंग ला पास, ऊपरी मुस्तांग, मुक्तिनाथ क्षेत्र, और घोडेपानी जैसे लोकप्रिय पर्यटकीय गंतव्य हैं। एसीएपी केवल विदेशी पर्यटकों के आंकड़े रखता है। यह क्षेत्र 7,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता, सांस्कृतिक विरासत और हिमालयी जीवन शैली के कारण विश्व स्तर पर एक प्रमुख ट्रेकिंग गंतव्य माना जाता है।

तरनतारन में छात्र ने क्लासरूम में घुसकर सिर में गोली मारी, खुद को भी शूट किया

तरनतारन। पंजाब के तरनतारन स्थित लॉ कॉलेज में सोमवार को छात्र ने क्लासरूम में घुसकर छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने वहीं पर खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मृतक छात्रा संदीप कौर (20) है, वह लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। वहीं आरोपी छात्र तरनतारन का प्रिंसराज सिंह है, वह भी छात्रा के साथ पढ़ता था। पुलिस ने लॉ कॉलेज को सील कर दिया है, साथ ही हत्या के कारणों की जांच कर रही है। वहीं लड़की की मां ने आरोप लगाया कि कॉलेज से उन्हें कहा गया कि छोटा सा झगड़ा हुआ और उनकी बेटी को चोट लगी है। वह कॉलेज पहुंचे तो बेटी मरी पड़ी थी। पुलिस जांच के मुताबिक मामला एकतरफा प्यार का है। लड़की की सगाई हो चुकी थी लेकिन लड़का उस पर दबाव डाल रहा था। पुलिस को ये भी शक है कि युवक ने वेलेंटाइन वीक में 8 फरवरी को छात्रा को प्रपोज किया था लेकिन उसने इनकार कर दिया। जब छात्रा राजी नहीं हुई तो छात्र ने ये कदम उठाया। कत्ल से जुड़ा कॉलेज के क्लासरूम का CCTV फुटेज सामने आया है। सोमवार सुबह 9 बजकर 16 मिनट पर क्लासरूम में सामान्य क्लास का माहौल है। तब क्लास में पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई थी। सभी स्टूडेंट क्लास में ही घूम रहे थे। इसी दौरान क्लासरूम की पिछली बैंच पर संदीप कौर अपनी सहेली के साथ बैठी होती है। उसी समय आरोपी लड़का भी वहां आकर पास में बैठ जाता है। वहां कुछ बात होती है। फिर थोड़ी देर में लड़का उठता है। वह अपने बैग में से पिस्टल निकालता है। इसके बाद वह छात्रा के सिर से पिस्टल सटाकर गोली मार देता है। गोली लगते ही छात्रा नीचे गिर पड़ती है। यह देख उसके साथ खड़ी सहेली भी हक्की-बक्की रह जाती है। वह संदीप कौर को संभालने के लिए झुकती, इससे पहले प्रिंसराज दोबारा पिस्टल लोड करता है और अपने सिर से सटाकर गोली मार देता है। इसके बाद वह भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद दूसरी छात्रा ने संदीप कौर को उठाने की कोशिश की, लेकिन पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारने की वजह से उसका ब्रेन फट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी।

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पारा माइनस 24°

नई दिल्ली/देहरादून/लखनऊ/शिमला/पटना। उत्तराखंड में आज 5 जिलों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं, पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में न्यूनतम तापमान माइनस 24°C रहा। राजस्थान के 10 से ज्यादा शहरों में टेंपरेचर 10° डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा सर्दी फतेहपुर और पाली में रही। इन शहरों का न्यूनतम तापमान 4.9°C और 5°C रहा। उत्तर प्रदेश के 19 और बिहार के 5 जिलों में आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में सुबह और देर रात विजिबिलिटी काफी कम हो सकती है। 9 से 11 फरवरी के बीच उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 10 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख जैसे क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

यूरेनियम इनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे: ईरान

एजेंसी, तेहरान

- डराकर हमसे कुछ नहीं करवाया जा सकता है, अमेरिका की नीयत पर भरोसा नहीं

ईरान ने अमेरिका के दबाव को सख्ती से खारिज करते हुए कहा है कि वो अपना यूरेनियम संवर्धन (यूरेनियम इनरिचमेंट) प्रोग्राम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे सैन्य धमकियां मिलें या नए प्रतिबंध लगाए जाएं। रविवार को तेहरान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान को डराकर उसकी परमाणु नीति नहीं बदली जा सकती और अमेरिका की मंशा पर हमें भरोसा नहीं है। यह बयान ऐसे समय आया है जब कई सालों बाद ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में बातचीत फिर से शुरू हुई है। ईरान चाहता है कि उस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटें, जबकि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक चाहता है।

अराघची बोले- ईरान को न बताए क्या करना है: अराघची ने साफ कहा कि यूरेनियम संवर्धन ईरान के लिए किसी भी हालत में समझौते का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह ईरान को बताए कि उसे क्या करना चाहिए, भले ही युद्ध की धमकी क्यों न दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती, जैसे कि USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी, ईरान को डराने में नाकाम रहेगी। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल है और यह साफ नहीं है कि वाशिंगटन सच में डिप्लोमेटिक हल चाहता भी है या नहीं। उन्होंने दोहराया कि ईरान ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा जो उसकी आजादी और सम्मान के खिलाफ हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रतिबंधों में राहत मिलती है तो ईरान भरोसा बढ़ाने वाले कुछ कदमों पर विचार कर सकता है, लेकिन यह सब आपसी सम्मान पर निर्भर करेगा।

ईरान पर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश का आरोप: पश्चिमी देश और इजराइल लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है, लेकिन ईरान इस बात से इनकार करता है। अराघची ने कहा कि ईरान किसी परमाणु बम की तलाश में नहीं है और उसकी असली ताकत बड़ी शक्तियों को 'न' कहने की क्षमता है। इस बीच अमेरिका, ईरान के आसपास लगातार अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। ईरान के साथ अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सलाहकार जारेड कुशनर ने कुछ समय पहले USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा किया था। अमेरिकी सेना ने कहा कि यह तैनाती सुरक्षा के लिए है और ट्रम्प की 'शांति के लिए ताकत' की नीति का हिस्सा है।

अमेरिका-ईरान ने पिछले हफ्ते न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत की: ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में न्यूक्लियर मुद्दे पर 6 फरवरी को बातचीत हुई थी। ट्रम्प ने इसे 'बहुत अच्छा' बताया था, जबकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियन ने इसे शांति के लिए 'एक कदम आगे' कहा था। लेकिन ट्रम्प ने बातचीत के तुरंत बाद एक आदेश जारी कर ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर नए टैरिफ लगाने की बात कही। इसके अलावा ईरानी तेल निर्यात से जुड़ी कंपनियों और जहाजों पर नए प्रतिबंध भी लगाए गए। अराघची ने कहा कि ऐसे कदम अमेरिका की गंभीरता पर सवाल खड़े करते हैं और ईरान इन्हीं संकेतों को देखकर तय करेगा कि बातचीत आगे जारी रखनी है या नहीं। यह पूरी प्रोसेस ऐसे समय चल रही है जब ईरान के अंदर हालात भी तनावपूर्ण हैं। दिसंबर के अंत से आर्थिक हालात और राजनीतिक मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें हिंसा हुई है। ईरानी सरकार का कहना है कि इन घटनाओं में 3,117 लोगों की मौत हुई है, जिनमें ज्यादातर सुरक्षाकर्मी और आम नागरिक थे।

नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने वाहन के नंबर प्लेट पर अंग्रेजी भाषा के उपयोग पर रोक लगाई

काठमांडू। सुप्रीम कोर्ट ने वाहन नंबर प्लेट पर अंग्रेजी भाषा का उपयोग न करने का अंतरिम आदेश जारी किया है। नंबर प्लेट में अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग से नेपाली मौलिक पहचान समाप्त होने का हवाला देते हुए लंबे समय से विरोध हो रहा था। अधिवक्ता रामबहादुर राउत ने प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय, भौतिक परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा परिवहन व्यवस्था विभाग को विपक्षी बनाकर यह रिट याचिका दायर की थी। इस रिट पर सुनवाई करते हुए सोमवार को न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल और कुमार रेग्मी की संयुक्त पीठ ने नंबर प्लेट पर अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया। राउत के अनुसार अदालत ने वाहन नंबर प्लेट में देवनागरी लिपि आधारित नेपाली अक्षरों और अंकों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का अंतरिम आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश ने नेपाल के सभी वाहनों पर नेपाली पहचान दर्शाने वाली देवनागरी लिपि के उपयोग के संवैधानिक अधिकार को पुनः स्थापित किया है। अधिवक्ता राउत ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद इसे सकारात्मक संदेश बताते हुए कहा कि यह नेपाली जनता की जीत है।

बलोचिस्तान पर विवादित टिपण्णी के लिए राणा सनाउल्लाह को सुनी पड़ी खरी-खोटी

एजेंसी, लाहौर

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार और पूर्व गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह को बलोचिस्तान में जबरन गायब किए जाए रहे लोगों के संबंध में की गई विवादास्पद टिप्पणी पर जमकर खरी-खोटी सुननी पड़ी। दो दिवसीय छठवें अंतरराष्ट्रीय अस्मा जहांगीर सम्मेलन में की गई इस टिप्पणी पर एक महिला ने तो यहां तक कह दिया कि राणा सनाउल्लाह 'तुम तो चुप ही रहो'। बलोचिस्तान से पहुंचे कई प्रतिनिधियों ने राणा की टिप्पणी पर कड़ा प्रतिवाद करते हुए सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया।

द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इसे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मानवाधिकार सम्मेलन माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय अस्मा जहांगीर सम्मेलन का समापन स्थानीय फलेटी होटल में आठ फरवरी को हुआ। प्रधानमंत्री के सलाहकार सनाउल्लाह राणा की टिप्पणी जमकर हंगामा हुआ। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। राणा ने बलोचिस्तान में लापता व्यक्तियों को बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) का समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि बीएलए से जुड़े लोगों ने मानवाधिकारों का कत्ल किया है। इसलिए ऐसे लोगों की जबरन उठा लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर आतंकवाद कायम रहेगा तो जबरन लोगों को गायब किया जाएगा

सम्मेलन में उपस्थित लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लोगों ने राणा सनाउल्लाह से हॉल से बाहर चले जाने की मांग की। वह अपने रुख पर अड़े रहे। इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। इसका विरोध करते हुए प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता शिमा किरमानी, बलोच सॉलिडेरिटी कमेटी के नेता और सामी दीन बलूच सहित आधे से ज्यादा वक्ता विरोध करते हुए हॉल से बाहर चले गए।

एपस्टीन फाइल्स-10 देशों में इस्तीफे, 80 ताकतवर लोगों की जांच, अमेरिका से यूरोप तक असर

एजेंसी, न्यूयॉर्क/नई दिल्ली

- राजनेताओं-अरबपतियों और शाही परिवारों तक फैली जांच

अमेरिका में यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज सामने आते ही दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने करीब 30 लाख पेज के डॉक्यूमेंट्स 30 जनवरी को जारी किए हैं। इसके बाद 10 देशों में 15 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ा है। 80 से ज्यादा ताकतवर लोगों पर जांच चल रही है। इन फाइलों में नेता, राजदूत, अरबपति और शाही परिवारों के नाम शामिल हैं। ईमेल, फ्लाइट लॉग और संपर्क रिकॉर्ड में 700 से 1000 असरदार लोगों का जिक्र है।

कई मामलों में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप भी हैं। दस्तावेजों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन जैसे हाई-प्रोफाइल नाम अलग-अलग संदर्भों में सामने आए हैं। एपस्टीन खुलासे के बाद सबसे ज्यादा हड़कंप यूरोप में है। करीब 10 देशों में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा ब्रिटेन में 3 अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ा। पूर्व राजदूत पीटर मैंडेलसन, सलाहकार एडम पेरी और पीएम कीर स्टार्मर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैकस्वीनी ने इस्तीफा दिया।

स्लोवाकिया में पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मीरोस्लाव लाइचाक ने 300 से अधिक ईमेल और आपत्तिजनक चैट सामने आने पर इस्तीफा दिया। स्वीडन की सीनियर डिप्लोमेट जोआना रुबिनस्टीन ने पद छोड़ा। नॉर्वे की राजदूत मोना जूल, अमेरिका में लेबर मिनिस्टर एलेक्स एकोस्टा और MIT लैब प्रमुख जोइची इतो ने इस्तीफा दिया।

एपस्टीन फाइल्स कई देशों की सरकारों के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक शर्मिंदगी का कारण बन गईं। ब्रिटिश पीएम स्टार्मर को माफी मांगनी पड़ी, जबकि प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ ब्रिटिश पुलिस ने नई फाइलों के आधार पर 'फ्रेश रिव्यू' शुरू किया।

नॉर्वे में राजदूत मोना जुएल को निलंबित किया गया और पूर्व पीएम थोरबजॉर्न जगलैंड के खिलाफ भ्रष्टाचार जांच शुरू हुई। सीनियर डिप्लोमेट तेर्झे रोड-लार्सन पर भी जांच चल रही है। फ्रांस में पूर्व मंत्री जैक लैंग को आधिकारिक समन जारी हुआ। पोलैंड, लातविया और तुर्किये ने मानव तस्करी के साथ आधिकारिक साठगांठ की जांच के लिए स्पेशल टीमें बनाईं।

राहुल बोले- स्पीकर ने कमिट किया, क्या आप बोलने देंगे

- रिजिजू बोले-कोई कमिटमेंट नहीं, लोकसभा स्थगित, विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है

एजेंसी, नई दिल्ली

बजट सत्र के 9 वें दिन लोकसभा की कार्यवाही केवल 13 मिनट ही चल पाई। विपक्ष सदन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने देने की मांग कर रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि 1 घंटा पहले स्पीकर के पास हम गए, स्पीकर ने हमें कमिट किया कि मुझे बजट डिस्कशन से पहले बोलने दिए जाएगा, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बोलने देंगी या नहीं। 3 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसंदी (स्पीकर की चेयर) पर संध्या राय (भाजपा सांसद) बैठी थीं।

राहुल की बात के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं भी स्पीकर के केबिन में मौजूद था। ऐसा कोई कमिटनमेंट नहीं किया गया। संध्या ने राहुल से कहा कि आपकी तरफ से किसी और मुद्दे के लिए कोई नोटिस नहीं आया है, बजट पर चर्चा करनी हो तो बताएं। इसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। वहीं, विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। न्यूज एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। यह प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। इसके लिए सदन में 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना होता है।

संसद और दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी

मेल में लिखा- 13 फरवरी को संसद में ब्लास्ट होगा, दिल्ली को खालिस्तान बना देंगे

एजेंसी, नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली के 15 स्कूलों को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिले। मेल में दावा किया गया कि 13 फरवरी को दोपहर 1.11 बजे संसद में ब्लास्ट होगा और दिल्ली को खालिस्तान बना देंगे। अधिकारियों ने बताया कि आठ धमकियां बाद में फर्जी पाई गईं। ईमेल में आतंकी अफजल गुरु और पंजाब को खालिस्तान बताने का भी जिक्र था। धमकी के बाद स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के मुताबिक, सुबह अलग-अलग इलाकों के स्कूलों से इमरजेंसी कॉल आईं। इसके बाद फायर टेंडर, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड तुरंत मौके पर पहुंची। धमकी भरे ईमेल में लिखा अफजल गुरु की याद में दिल्ली बनेगा खालिस्तान। 1:11 बजे पर धमाका होगा, 13 फरवरी को 1:11 बजे पर संसद में ब्लास्ट होगा। पंजाब खालिस्तान है। खालिस्तान नेशनल आर्मी।

स्कूलों को खाली कराया गया: DFS के एक अधिकारी ने कहा कि अब तक 15 स्कूलों ने धमकी मिलने की सूचना दी है। सभी परिसरों की गहन जांच की जा रही है। इनमें से आठ धमकियों को बाद में फर्जी बताया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ईमेल की लोकेशन और सोर्स पता करने के लिए साइबर टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। साथ ही राजधानी के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। अब तक किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।

फरीदाबाद जेल में आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या

एजेंसी, फरीदाबाद

हरियाणा की फरीदाबाद जेल में बंद आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई है। रविवार देर रात जेल में मर्डर केस में बंद अरुण चौधरी उर्फ अब्बू जट नाम के कैदी ने उस पर नुकीली चीज से हमला किया। दोनों को हाई सिक्योरिटी वाली बैरक में एक साथ बंद किया गया था। कत्ल का पता चलते ही जेल अधिकारी बैरक में पहुंचे। इसके बाद आतंकी की लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया गया। 20 साल के आतंकी अब्दुल को गुजरात ATS ने मार्च 2025 में पकड़ा था। जांच में पता चला कि वह अलकायदा इन इंडियन सब-कांटिनेंट (AQIS) के कुख्यात आतंकी अबू सूफियान के संपर्क में था। उसने अयोध्या में राम मंदिर उड़ाने की साजिश रची थी।

वहीं कत्ल करने वाला कैदी अरुण चौधरी का नाम भी चर्चित अक्षय शर्मा हत्याकांड में आया था। उसे पंजाब में हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 2 साल पहले ही उसे कठुआ जेल से फरीदाबाद की इस नीमका जेल में शिफ्ट किया गया था। सांबा में अक्षय शर्मा हत्याकांड से चर्चा में आया: आतंकी की हत्या करने वाला अरुण चौधरी जम्मू जिले के आरएस पुरा सेक्टर के गांव खौर देओनियन का रहने वाला है। उसका नाम दिसंबर 2023 में हुए सांबा निवासी अक्षय शर्मा हत्याकांड के बाद चर्चा में आया था। वर्ष 2023 में पंजाब में हुई मुठभेड़ के बाद अरुण चौधरी को गिरफ्तार किया गया था।

अमेरिकी सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटी, 50 की जगह 25% की न्यूजीलैंड-ईयू के बाद इंडो-यूएस ट्रेड डील से बागवान चिंतित

एजेंसी, शिमला

अमेरिकी सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत और न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) 80 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अब अमेरिकी सेब भारत में लगभग 100 रुपए प्रति किलो की दर से पहुंचेगा। केंद्र सरकार इससे पहले न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन (EU) के सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी 50 फीसदी से क्रमशः 25 व 20 फीसदी कर चुकी है। अब अमेरिकी सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने से हिमाचल के सेब बागवानों की चिंताएं और बढ़ गई है। इसका सीधा असर हिमाचल के 5500 करोड़ रुपए के सेब उद्योग पर पड़ेगा। विदेशों से अब सस्ता सेब देश के बाजारों में आएगा। इससे हिमाचल समेत जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब को अच्छे रेट नहीं मिल पाएंगे।

हिमाचल का सेब बुरी तरह पिटेगा: महेंद्र: सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष महेंद्र वर्मा ने बताया कि वाशिंगटन एपल के भारतीय बाजारों में आने से हिमाचल का प्रीमियम क्वालिटी का सेब बुरी तरह पिट जाएगा। सेब बागवानों को अच्छे सेब के दाम नहीं मिल पाएंगे। उन्होंने बताया कि वाशिंगटन एपल की ज्यादा मार प्रिमियम सेब और कोल्ड स्टोर में रखे एपल पर ज्यादा पड़ेगी। उन्होंने केंद्र सरकार इस दावे को खारिज किया कि इस समझौते से पहले अमेरिकी सेब 75 रुपए प्रति किलो की दर से भारत पहुंच रहा था। उन्होंने सवाल किया यदि अमेरिकी सेब 75 रुपए में आ रहा था, तो बाजार में वह 200 से 250 रुपए प्रति किलो कैसे बिक रहा था?

प्रीमियम सेब पर ज्यादा मार पड़ेगी: बिष्ट: प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स एसोसिएशन (PGA) के अध्यक्ष लोकिंदर बिष्ट ने बताया कि प्रीमियम क्वालिटी सेब पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन 25 प्रतिशत आयात शुल्क और 80 रुपए का MIP कुछ हद तक स्थानीय सेब अर्थव्यवस्था को बचाएगा। उन्होंने बताया कि MIP कम से कम 100 रुपए होना चाहिए था, ताकि स्थानीय बागवानों को और सुरक्षा मिलती। बिष्ट ने कहा कि स्थानीय प्रीमियम सेब की कीमत अमेरिकी सेब से ज्यादा नहीं रह पाएगी। यदि हमारे प्रीमियम सेब की कीमत गिरेगी, तो इसका असर निम्न गुणवत्ता वाले सेब पर भी पड़ेगा।

विकसित भारत 2047 और सुशासन का संकटः -निर्धारित ड्रेसकोड पहचान पत्र नदारद- अनुशासन,जवाबदेही और प्रशासनिक संस्कृति का वैश्विक परिप्रेक्ष्य -एक समग्र विश्लेषण

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

- देश क़ी राज्य सरकारों को पंजाब दिल्ली और क़ा सरकार तुहाडे द्वार व डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज यह मॉडल अपनाने की खास जरूरत है
- सरकारी दफ्तरों के चक्कर, अनसुनी शिकायतें,बिना पहचान आईकार्ड के कर्मचारी, ड्रेस कोड का उल्लंघन, फाइलों का महीनों लंबित रहना और जवाबदेही का अभाव दुर्भाग्यपूर्ण -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।पीएम से लेकर केंद्र और राज्य स्तर केप्रत्येक मंत्री के भाषणों में विकसित भारत एक केंद्रीय संकल्प के रूप में उभरकर सामने आता है। इस संकल्प के चार प्रमुख स्तंभ, तकनीकी नवाचार,आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और सुशासन भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाले तत्व माने जा रहे हैं।इनमें से सुशासन वह आधार है, जिसपर बाकी सभी स्तंभ टिके होते हैं।किंतु जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी और न्यायालयीन कार्यालयों में व्याप्त अनुशासनहीनता, कमजोर दंड व्यवस्था और कार्य-संस्कृति की गिरावट इस सपने को खोखला करने का कार्य कर रही है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि भारत के आम नागरिक के लिए सुशासन कोई सैद्धांतिक शब्द नहीं,बल्कि रोज़मर्रा का अनुभव है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर, अनसुनी शिकायतें,बिना पहचान आईकार्ड के कर्मचारी, ड्रेस कोड का उल्लंघन, फाइलों का महीनों लंबित रहना और जवाबदेही का अभाव। यह स्थिति केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विश्वास के क्षरण का संकेत है।दूसरी तरफ दिल्ली और पंजाब की सरकार प्रमुखता से सरकार तुहाडे द्वार व सरकार आपके द्वार के माध्यम से घर -घर सेवाएं प्रदान कर रही है।इस पहल के तहत, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब में 10 दिसंबर 2023 से 43 सरकारी सेवाएं नागरिकों के घर तक पहुंचाई जा रही हैं, जिसमें दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इस तर्ज पर पूरे देश क़ी राज्य सरकारों को यह मॉडल अपनाने की खास जरूरत है। साथियों बात अगर हम सुशासन की अवधारणाः अंतरराष्ट्रीय मानकों में भारत कहां खड़ा है इसको समझने की करें तो विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और ओसीईडी जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अनुसार सुशासन के प्रमुख तत्व हैं,पारदर्शिता,जवाबदेही,कानून का शासन,दक्षता और नागरिक- केन्द्रित सेवाएं। विकसित देशों में सरकारी कर्मचारी केवल सेवा प्रदाता नहीं,बल्कि सार्वजनिक विश्वास के संरक्षक माने जाते हैं।वहां ड्रेस कोड,पहचान पत्र, समयबद्ध सेवा और व्यवहारिक शिष्टाचार अनिवार्य प्रशासनिक अनुशासन का हिस्सा हैं।इसके विपरीत भारत में अनेक सरकारी और न्यायालयीन कार्यालयों में कर्मचारी न तो निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करते हैं, न ही पहचान पत्र प्रदर्शित करते हैं।यह केवल एक औपचारिक कमी नहीं,बल्कि सत्ता और नागरिक के बीच असमानता की मानसिकता को दर्शाता है, जहां कर्मचारी स्वयं को जवाबदेह नहीं मानता।

साथियों बात अगर हम अनुशासन हीनताः विकसित भारत की सबसे बड़ी आंतरिक बाधा इसको समझने की करें तो,अनुशासन किसी भी संगठन की रीढ़ होता है,विशेषकर शासन व्यवस्था में। किंतु भारत के शासकीय कार्यालयों में अनुशासन की भारी कमी एक सामान्य दृश्य बन चुकी है। कार्यालय समय का पालन न करना,नागरिकों से असम्मानजनक व्यवहार, नियमों की खुली अवहेलना और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आंख मूंद लेना ये सभी प्रशासनिक विफलता के स्पष्ट संकेत हैं।न्यायालयीन परिसरों में भी स्थिति भिन्न नहीं है। न्याय के मंदिरों में यदि अनुशासन और पारदर्शिता ही कमजोर हो, तो आम नागरिक का न्याय प्रणाली पर विश्वासडगमगाना स्वाभाविक है। विकसित राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। साथियों बात अगर हम कमजोर दंड व्यवस्था और दण्डहीनता की संस्कृति इसको समझने की करें तो प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन तभी रुकता है जब उसके परिणाम स्पष्ट और कठोर हों। भारत में समस्या यह नहीं है कि नियम नहीं हैं, बल्कि यह है कि नियमों के उल्लंघन पर दंड की प्रक्रिया कमजोर,धीमी और अक्सर राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव से प्रभावित रहती है। जब कर्मचारी जानते हैं कि ड्रेस कोड न मानने, पहचान पत्र न लगाने या नागरिकों को परेशान करने पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी,तो अनुशासन स्वतः समाप्त हो जाता है। दण्डहीनता की यह संस्कृति सुशासन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। साथियों बात अगर हम फाइल संस्कृति,देरी और प्रशासनिक उदासीनता इसको समझने की करें तो फाइल लंबित है भारत की शासन व्यवस्था का सबसे कुख्यात वाक्य बन चुका है। समय पर काम न होना, अनावश्यक प्रक्रियाएं और कर्मचारियों की उदासीनता न केवल आर्थिक विकास को धीमा करती हैं,बल्कि नागरिकों को मानसिक,सामाजिक और आर्थिक पीड़ा भी देती हैं।अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है कि विकसित देशों में प्रशासनिक दक्षता को मापा जाता है,प्रत्येक सेवा की समय सीमा तय होती है और विलंब के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है। भारत में अभी भी यह संस्कृति व्यापक रूप से विकसित नहीं हो पाई है। साथियों बात अगर हम नौकरशाही का दबदबा और नागरिक-केन्द्रित शासन का अभाव इसको समझने की करें तो भारत की शासन व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से औपनिवेशिक नौकरशाही से प्रभावित रही है, जहां प्रशासन शासक-केन्द्रित था, नागरिक- केन्द्रित नहीं। आज़ादी के दशकों बाद भी यह मानसिकता पूरी तरह बदली नहीं है। कई सरकारी कार्यालयों में नागरिक को याचक की तरह देखा जाता है, जबकि वास्तव में वह करदाता और अधिकारधारी है।विकसित भारत की परिकल्पना तभी साकार होगी जब प्रशासन स्वयं को सेवा प्रदाता और नागरिक को ग्राहक नहीं, बल्कि साझेदार माने।

साथियों बात अगर हम राजनीतिक हस्तक्षेप और जवाबदेही का संकट इसको समझने की करें तो,सुशासन की राह में राजनीतिक हस्तक्षेप एक और बड़ी बाधा है। जब अनुशासनात्मक कार्रवाई राजनीतिक दबाव में कमजोर पड़ती है, तो संदेश स्पष्ट होता है नियम सभी पर समान रूप से लागू नहीं होते। यह स्थिति प्रशासनिक मनोबल को भी कमजोर करती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो मजबूत लोकतंत्र वही हैं।जहां प्रशासनिक निर्णय कानून और नियमों के आधार पर होते हैं, न कि राजनीतिक संरक्षण पर। साथियों बात अगर हम विकसित भारत के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुधार को समझने की करें तो विकसित भारत 2047 केवल आर्थिक आंकड़ों का लक्ष्य नहीं, बल्कि प्रशासनिक संस्कृति के परिवर्तन का मिशन है। इसके लिए सबसे पहले कार्यकुशलता में सुधार आवश्यक है। सरकारी और न्यायालयीन प्रक्रियाओं का व्यापक डिजिटलीकरण, समयबद्ध सेवाएं और प्रदर्शन- आधारित मूल्यांकन अनिवार्य होना चाहिए। डिजिटल गवर्नेंस केवल तकनीक नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही का माध्यम है।जब हर प्रक्रिया ट्रैक होती है, तो अनुशासन स्वतः मजबूत होता है।

साथियों बात अगर हम अनुशासन लागू करने के लिए कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई को समझने की करें तो अनुशासन बनाए रखने के लिए नियमों का सख्ती से पालन और उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। ड्रेस कोड, पहचान पत्र और नागरिक व्यवहार जैसे बुनियादी नियमों की अनदेखी पर केवल कर्मचारी ही नहीं, बल्कि संबंधित अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।नियमों का पालन सुझाव नहीं, बल्कि अनिवार्यता होना चाहिए।यही विकसित शासन व्यवस्था की पहचान है।प्रशिक्षण, नैतिकता और कार्य-संस्कृतिप्रशासनिक सुधार केवल दंड से नहीं, बल्कि प्रशिक्षण से भी आता है। कर्मचारियों के लिए नैतिक, व्यवहारिक और कार्य-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य किए जाने चाहिए। उन्हें यह समझाना आवश्यक है कि वे सत्ता के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि सार्वजनिक सेवा के वाहक हैं।विकसित देशों में सरकारी सेवा को पब्लिक ट्रस्ट माना जाता है। भारत को भी इसी दिशा में अपनी प्रशासनिक संस्कृति को पुनर्गठित करना होगा। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि विकसित भारत का रास्ता अनुशासन से होकर जाता है,विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब सुशासन केवल भाषणों का विषय न रहकर, कार्यालयों की कार्य-संस्कृति में दिखाई दे। ड्रेस कोड से लेकर जवाबदेही तक, पहचान पत्र से लेकर समयबद्ध सेवा तक ये सभी छोटे दिखने वाले तत्व वास्तव में राष्ट्र निर्माण की नींव हैं।यदि प्रशासनिक अनुशासन, दंड व्यवस्था और नागरिक- केन्द्रित दृष्टिकोण में त्वरित और ठोस सुधार नहीं हुए, तो तकनीकी नवाचार और आर्थिक विकास भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएंगे।विकसित भारत का मार्ग केवल बड़े विज़न से नहीं, बल्कि छोटे-छोटे प्रशासनिक सुधारों से होकर गुजरता है,और यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

-संकलनकर्ता लेखक-कर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
9226229318

त्वरित विकास को समर्पित कल्याणकारी केन्द्री य बजट

लेखक - डॉ. महेन्द्र सिंह

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए संसद में पेश किया गया गया बजट देश के त्वरित विकास को समर्पित कल्याणकारी बजट है। इस बजट में समाहित प्रस्तावों में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने और उसे निरन्तर बनाये रखने पर जोर दिया गया है। साथ ही, लोककल्याण के लिए बजट प्रस्तावों पर भी पर्याप्त बल दिया गया है। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में तीन कर्तव्यों को उजागर किया। ये हैं : ( ) अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के प्रति लचीलेपन में वृद्धि करते हुए आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे बनाये रखना; (ii) जन आकाँक्षाओं की पूर्ति और उनकी क्षमताओं का वर्द्धन करना एवं (iii) देश के प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और वर्ग तक संसाधनों, सुविधाओं तथा अवसरों की पहुंच को सुनिश्चित करना। इस तरह ये कर्तव्य मोदी सरकार की सर्वसमावेशी एवं पोषणीय विकास की रणनीति को सुस्पष्ट रूप में परिभाषित करते हैं। ध्यातव्य है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के केन्द्र में एक ओर आर्थिक संवृद्धि की गति को तेज करना रहा है वहीं दूसरी तरफ सापेक्षतया वंचित लोगों एवं क्षेत्रों को उनकी क्षमता व सामर्थ्य को बढ़ाते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करना रहा है। इस दृष्टि से यह कहना समीचीन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास का ध्येय वाक्य लोकनीतियों के प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन का नाभिकेन्द्र रहा है। इसमें आर्थिक समृद्धि एवं लोककल्याण में वृद्धि स्वतः विहित रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा संरचनात्मक आर्थिक सुधारों का मूल विचार रिफार्म, परफार्म व ट्रॉन्सफार्म रहा है। इस बजट में भी, बजट प्रावधानों को अधिक परिणामोन्मुखी बनाने के लिए सुधारों के क्रम को जारी रखा गया है। विकसित भारत के महालक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस बजट में कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र, एमएसएमई, ओडीओपी, रिन्यूबल व न्यूक्लियर एनर्जी, सेमिकंडक्टर, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, जलमार्ग व रेल विकास, डिकार्बनाइजेशन, निर्यात संवर्द्धन, रक्षा क्षेत्र इत्यादि संभावनापूर्ण क्षेत्रों एवं तत्सम्बन्धी क्रियाओं के संवर्द्धन व विकास के लिए वित्तमंत्री द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित आवंटन किए गये हैं। साथ ही, मानव पूँजी के निर्माण से सम्बन्धित क्षेत्रों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, युवा और दिव्यांग सशक्तिकरण पर पर्याप्त बल दिया गया है। वस्तुतः, मानव पूँजी के बेहतर विकास से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा जनकल्याण में वृद्धि होगी। वित्तमंत्री ने इस बजट में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को जारी रखते हुए इस पर विशेष बल दिया है। हाल के वर्षों में जीडीपी के सापेक्ष राजकोषीय घाटा में निरन्तर गिरावट से इस बात की पुष्टि होती है कि मोदी सरकार का राजकोषीय प्रबन्धन सम्बन्धी निष्पादन श्लाधनीय रहा है। वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.7 प्रतिशत; 2022-24 में 6.5 प्रतिशत 2023-24 में 5.5 प्रतिशत; 2024-25 में 4.8 प्रतिशत एवं 2025-26 में 4.4 प्रतिशत था। इसे 2026-27 के बजट में कम करके 4.3 प्रतिशत पर रख गया है। ये प्रवृत्तियाँ राजकोषीय व्यवस्था की मजबूती की परिचायक हैं। मोदी सरकार की राजकोषीय प्रवीणता एवं बेहतर वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है कि जीडीपी के सापेक्ष राजकोषीय घाटा निरन्तर घटा है। साथ ही, वित्तमंत्री इस बात में भी सफल रही हैं कि उन्होंने इस बजट में जीडीपी के सापेक्ष केन्द्र सरकार के ऋण को 55.6 प्रतिशत पर रखा है। यह वर्ष 2025-26 के लिए 56.1 प्रतिशत रखा गया था। साथ ही, इस बजट में जीडीपी के सापेक्ष राजस्व घाटा एवं प्राथमिक घाटा में भी कमी आई है। घटते घाटे एवं ऋण से निजी पूँजी निवेश में वृद्धि होगी। इस बजट में, राजस्व में सतत वृद्धि; पूँजीगत व्यय में वृद्धि और राजकोषीय पारदर्शिता में सुधार के संकेतकों से भी देश की राजकोषीय सुदृढ़ता की पुष्टि होती है। पूँजीगत खर्च के जरिये अवस्थापना क्षेत्र के विकास ने विकास को तेज करने और रोजगार को बढ़ाने में उल्लेखनीय तौर पर योगदान दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक विकास में धमनियों का कार्य करता है। इसलिए यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर मोदी सरकार द्वारा किया गया निवेश लगातार विकास का इंजन बना हुआ है।

रेडिकल नारीवाद का प्रकृति विरूद्ध दर्शनःएक विश्लेषण

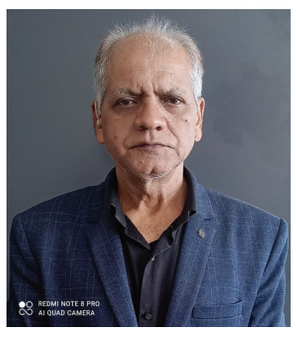

राजेश पाठक

आधुनिक रेडिकल नारीवादी सिद्धांत की उपज 1949 में प्रकाशित फ्रांसीसी अस्तित्ववादी दार्शनिक सिमन द बाऊवार की पुस्तक "द सेकेंड सेक्स" है जिसने पुरुष संस्कृति के मूल्यों को चुनौती दी। अति नारीवादियों का मानना है -'स्त्री को उसके संपूर्णता के साथ स्वीकारने का साहस दिखाना ही होगा।' इस संदर्भ में तथ्य यह है कि उन्हें इस बात का भान होना चाहिए कि नारी अपने आप में तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक वह पुरूष के साथ तन-मन से संबद्ध न हो जाए। परंतु इसका आशय यह बिल्कुल नहीं कि पुरूष नारी के बिना पूर्ण है। सच कहूं तो यहां बात पूर्णता या अपूर्णता की न होकर निम्नतर या श्रेष्ठतर की है जिसे नारीवादी सहज भाव से अभिव्यक्त करते हैं। अति नारीवादी सोच सामान्य एवं सहज भाव से जिंदगी गुजार रही नारियों के मस्तिष्क में पुरूष वर्ग के विरूद्ध जबरन ठूंस दिया जाने वाला एक दर्शन मात्र है जिसे आज की प्रबुद्ध स्त्रियां महसूस करने लगी हैं। उन्हें लगने लगा है कि निम्नतर और श्रेष्ठतर की प्रास्थिति विभिन्न काल, समय एवं अवस्थाओं के अनुरूप बदलते रहती है। अफसोस कि अति नारीवादी स्त्रियों के सर्वस्व न्योछावर करने के सहज, प्राकृतिक गुण को 'पुरूषों का दासत्व स्वीकारना' कहते हैं। न्यौछावर दासत्व नहीं 'अपनत्व' एवं 'स्वत्व' का बोध कराता है जिसकी तात्विक अनुभूति विरले ही कर पाते हैं।अति नारीवादियों द्वारा यह भी तर्क दिया जाता रहा है कि स्त्री स्वंय के प्रकृति की सर्वोच्च रचना होने के एहसास से अछूती रही, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। ज्ञात हो कि स्त्री, पुरूष की भांति ही प्रकृति की एक रचना है न कि सर्वोच्च रचना, जिन्हें स्थिति एवं परिस्थिति के अनुसार निम्न या सर्वोच्च-दोनों ही अवस्थाओं से गुजरने का अवसर सदैव मिलता रहता है। कभी स्त्री तो कभी पुरूष एक दूसरे से निम्नतर या श्रेष्ठतर प्रास्थिति को प्राप्त करते रहते हैं। यह प्रास्थिति कभी भी स्थायी प्रकृति की नहीं होती क्योंकि समय एवं काल गतिमान होता है। समय के साथ साथ परिस्थितियों, सामाजिक रचनाओं-संरचनाओं में क्रमिक एवं मौन क्रांति सदैव होते रहती है जिसे निकट दृष्टिदोष वाला व्यक्तित्व सहजता एवं सरलता से महसूस नहीं कर पाता है एवं विभ्रम की स्थिति में रह जाता है। इतना ही नहीं, अति नारीवादी दर्शन के समर्थकों का कहना है - ''स्तन स्त्री काया के अलंकार हैं, आभूषण है। उसके आकर्षण का केन्द्रक है।" मैं जानता चाहता हूं कि क्या वे बता सकते हैं कि स्त्रियों के उस आभूषण के प्रति किसके आकर्षित होने की बात की जाती है ? मेरा मानना है कि उस आभूषण के प्रति अन्य स्त्रियां एवं अन्य पुरूष, दोनों ही आकर्षित हो सकते हैं परंतु विपरीत लिंगों का एक-दूसरे के प्रति आकर्षण भी सहज एवं प्राकृतिक गुणधर्म वाली बात होती है। मैं स्त्रीवादी एवं पुरूषवादी, दोनो ही सोच को प्रकृति विरूद्ध मानता हूं। सोच मानवतावादी ही स्वीकार्य होनी चाहिए और मानववादी सोच दोनों के आपसी सामंजस्य, समर्पण एवं त्याग जैसे अति संवेदनशील गुणों की पैरवी करती है। मानव सभ्यता के प्रारंभ में मातृसत्तात्मक व्यवस्था ही समाज में प्रचलित हुई। उस समय समाज की मौलिक विशेषताओं में अस्थायी विवाह संबंध, स्त्री के माध्यम से संबंधों की पहचान करना तथा संपत्ति और शक्ति पर केवल स्त्रियों का उत्तराधिकार शामिल थे। अधिकांश आदिम जातियां, खासकर आस्ट्रेलिया और मलय द्वीप समूहों की आदिम जातियां, अपने समाज में बहुपतित्व यानी पॉलन्ड्री एवं अस्थायी विवाह संबंधों को अपनी सभ्यता की पृथक पहचान देने में लगे थे। इतना ही नहीं, उस समय 'बीमाह-विवाह' प्रचलन में था जिसके अनुसार पति को पत्नी के ही परिवार में शामिल कर लिया जाता था। इन परिस्थितियों में वंशानुक्रम का निश्चय माता के ही माध्यम से होता था। आज अति नारीवादी अवधारणा के बलवती होने का परिणाम ही है कि जीव वैज्ञानिकों का ध्यान पुरूषों में कोख प्रतिरोपण एवं शिशु जनन की दिशा की ओर आकृष्ट हुआ है। इस बिंदु पर शोध भी जारी है। शोध के सफल होने के बाद इसे व्यवहार मे लाने के लिए समाज एवं कानून की मान्यता की जरूरत होगी। वस्तुतः जीव वैज्ञानिकों द्वारा उपयुक्त शोध किया जाना एक अलग विषय है एवं उसे समाज एवं कानून द्वारा मान्यता मिलना एक पृथक विषय क्योंकि विज्ञान जीवों के परिष्करण एवं उनके समुन्नत कार्य व्यवहार की प्रणाली विकसित करने में अपने अस्तित्व को समाज में प्रतिष्ठापित करने का भरसक प्रयत्न करता है।पुनः रेडिकल नारीवादी दृष्टिकोण के हिमायती का यह कहना कि स्त्रियां यौनानंद वह चरमसुख की बजाए कोख में तब्दील होने को लालायित हो उठती हैं, समाज में विभ्रम पैदा करने के लिए काफी है। उन्हें मालूम हो कि प्रकृति ने मानव जाति में स्त्री और पुरूष जाति का निर्माण कर एक में कोख धारण की क्षमता प्रदान की एवं दूसरे में नहीं। क्या होता जब एक ही वर्ग-समूह में शुक्राणु एवं अंडाणुओं की जैविक व्यवस्था होती ? यह तो प्रकृति है जिसने यह महसूस किया कि परस्पर निर्भरता जीवों के संयत संचालन का एक अपरिहार्य तत्व है एवं तदनुरूप वह वैसी व्यवस्थाऐं स्त्री एवं पुरूष वर्ग में अधिरोपित कर पायी। अब व्यक्त आ गया है कि मानवजाति एक-दूसरे की निम्नतर या श्रेष्ठतर अवस्थाओं रूपी दुष्चक्र से बाहर हो परस्पर निर्भरता की अनिवार्यता को महसूस करे क्योंकि पारस्परिक समपर्ण भाव में जहां श्रेष्ठता का भाव छिपा रहता है वही ऐसे सम्यक गुणों को धारण करने वाले व्यक्तित्व ही जीवन के मूल उद्देश्यों को भली-भांति अपने हृदय में आत्मसात कर पाते हैं एवं ब्रह्मांड की अतिशय विशिष्ट अनुकृति यानी मानव रचना का अनुरक्षण एवं पोषण करते हुए सदकर्म एवं जीवों की प्रभावशीलता को उसकी श्रेष्ठता का आधार स्वीकार करते रहते हैं जो कि प्रकृति विरोधी न होकर 'प्रकृति मित्र' प्रतीत होता है। जिस वैदिक काल में वर्णित तथ्यों का जिक्र करते हुए तर्क दिया जाता है उस काल की स्त्रियां इस सत्य के ज्यादा निकट हुआ करती थीं कि शौर्यवान, वीर्यवान एवं ज्ञानी पुरूषों के सहवास से उन्हीं के समान प्रकृति वाला पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी जो समाज में राक्षसी प्रवृति वाले संवेदनहीन जनों से सभ्यता एवं समाज की रक्षा कर पाएंगे। इसके साथ ही यह धारणा उस समाज में ज्यादा बलवती थी कि स्त्रियों द्वारा याचित कामना की पूर्ति करने में सक्षम पुरूष यदि जान-बूझ कर उनकी कामना की पूर्ति नहीं करता है तो उसे भी एक प्रकार से स्त्रियों के अपमान का दंश झेलना पड़ता था। परंतु ठीक इसके विपरीत पुरूषों द्वारा याचित इसी प्रकार की कामना की पूर्ति करने की स्वतंत्रता स्त्रियों को प्राप्त नहीं थी। पुरूषों के इस ढंग की कामना को पाप समझा जाता था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी-न-किसी रूप में इस तथ्य को हम बहुपतित्व प्रथा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। महाभारत काल में भी द्रौपदी को बहुपतित्व प्रथा की अनुगामी माना जा सकता है। यह विडंबना ही है कि जब एक स्त्री एक से अधिक पतिगामी होती थी तो उस प्रथा को भी रेडिकल नारीवादी सोच रखने वाले स्त्रियों का शोषण ही मानते हैं और इसके विपरीत वर्तमान समाज में जब एक पुरूष एक से अधिक पत्नी का सहगामी बनता है तब उसे पुरूषों द्वारा स्त्रियों का शोषण तो मानते ही हैं। उनका यह कहना- 'टेसुए बहाते रहने और पुरूषों से भीख में दया मांगते रहने से संबल नहीं मिलेगा' आज उतना प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता। आज स्त्रियां कानून से इतनी संरक्षित है कि पुरूष सामान्य अवस्था में उससे अंदर -ही-अंदर भयभीत ही रहता है। आज का यह भी एक स्याह पक्ष है कि औरतें स्त्री सुरक्षा के लिए बनाये गए कानूनों की आड़ में गलत ढंग से लाभ लेकर पुरूषों को अपमानित, तिरष्कृत करने तथा मुद्रामोचन-भयादोहन करने से भी गुरेज नहीं करतीं। यद्यपि यह अवस्था अभी परिपक्व नहीं हुई है तथापि इसके बीजारोपण परिणामस्वरूप समाज में स्त्री-पुरूष के बीच एक 'अदृश्य अविश्वास' का वातावरण निर्मित होने लगा है। कुल मिलाकर यह समझा जाना चाहिए कि वैचारिक भिन्नताएं अस्तित्व में रहते हुए भी स्त्रियों-पुरूषों के बीच प्राकृतिक रूप से व्याप्त असमानताओं के समूल उन्मूलन की हठधर्मिता समाज के ताने बाने को ही न छिन्न भिन्न कर दे। कानून और समाज की सहज स्वीकृति के दायरे में रहते हुए अति नारीवादी दर्शन में भी नयी प्रणाली का अनुसंधान अपेक्षित है ताकि सामाजिक-आर्थिक संस्कृति अक्षुण्ण रहे।

(लेखक झारखंड सरकार के योजना एवं विकास विभाग में सांख्यिकी अधिकारी हैं)

अमर शहीद राजा सरयू प्रसाद सिंह, और क्रान्ति का गढ़ विजय राघव गढ़

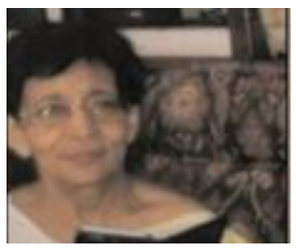

डॉ.जया शुक्ला

स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृतियों के साथ कितनी अधिक बेपरवाही बरती गई है, इसका बड़ा उदाहरण विजय राघव गढ़ का खंडहरों में तब्दील होता ऐतिहासिक दुर्ग है। सन् 1857 में मेरठ से सैनिकों में विद्रोह की आँच सुलगनी प्रारंभ हो चुकी थी। उन्हें पता चल चुका था कि बन्दूक की गोलियाँ, जिन्हें इस्तेमाल के पूर्व दाँत से खोलना पड़ता था, उनपर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, जो हिन्दू-मुस्लिम दोनों धर्मों के लिये वर्जित थी। पूरे देश मे फिरंगियों के विरुद्ध रियासतों में क्रांति की ज्वाला सुलग रही थी। अंग्रेज़ अपने फ़ायदे के लिये तरह तरह के नियम-क़ानून बना कर भारतीय रियासतों को हड़पने की कोशिश कर

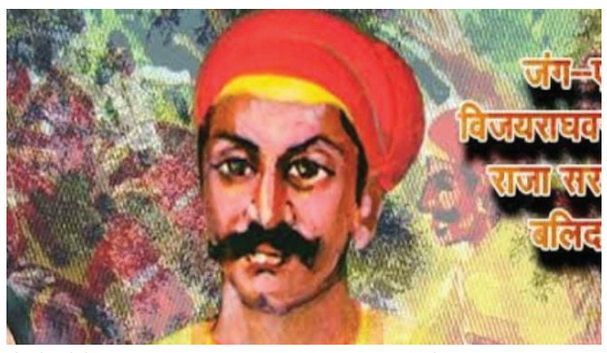

रहे थे। ऐसे समय 8 अगस्त, 1857 को विजय राघव गढ़ रियासत के राजा सरयू प्रसाद सिंह केदुर्ग में सुपुत्र का जन्म हुआ। अंग्रेजो ने झाँसी और विजय राघव गढ़ रियासतों को कोर्ट ऑफ वॉर्ड के अंतर्गत अधिगृहीत कर दोनों रियासतों पर अपने अधिकारियों को बैठाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया था। नवजात के जन्मोत्सव के लिये राजा सरयू प्रसाद सिंह ने नियमानुसार ब्रिटिश हुकुमत से राशि की मांग की थी। किन्तु अल्प राशि स्वीकृत होने के कारण सरयू प्रसाद सिंह का राजपूत रक्त खोल उठा और उन्होंने अंग्रेज़ अफ़सर मीर साबित अली की गोली मारकर हत्या कर दी। यहीं से 1857 की क्रांति की जो ज्वाला जल रहीं थी, वह पूरे ज़ोर से भड़क उठी। 17 वर्षीय सरयू प्रसाद सिंह को अभी भूगोल का भी छीक से ज्ञान नहीं था, परन्तु उन्होंने अंग्रेजो के विरुद्ध क्रांति का बिगुल फूँक दिया। महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राजा सरयू प्रसाद सिंह ने गुप्त पत्राचार द्वारा मध्य भारत में क्रांति की बागडोर अपने हांथों में लेकर क्रांति का बिगुल फूँक दिया, और अंग्रेजो को खुली चुनौती दे दी। जबलपुर में विद्रोही रघुनाथ शाह तथा उनके बेटे को तोप से बाँधकर अंग्रेज़ों ने उड़ा दिया। इससे क्षुब्ध होकर राजा सरयू प्रसाद सिंह ने उत्तर भारत

को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला एन ch 7 जबलपुर मिर्जापुर जाने वाला मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिससे अंग्रेजो की संचार व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। अंग्रेज़ तिलमिला गये। कर्नल व्हिसलर ने अवध, इलाहाबाद, नरसिंहपुर, नागपुर, सागर की अँग्रेज़ी सेनाओं को विजय राघव गढ़ पर आक्रमण का आदेश देकर सरयू प्रसाद सिंह के किले को नेस्तनाबूद करके उन्हें मार डालने का फ़रमान ज़ारी कर दिया। विजय राघव गढ़ रियासत को अंग्रेज़ी सेनाओं ने चारों दिशाओं से अक्टूबर के महीने तक घेरलिया, और हमला बोल दिया। किन्तु राजा सरयू प्रसाद सिंह ने अपने दुधमुँहे बालक को लेकर विंध्य के जंगलों में शरण ले ली थी। वह ग़दर की विभिन्न गतिविधियों में लगे रहे। किन्तु बाद में पकड़े गए। 1865 में उन्हें अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दी, और उनके बालक ठाकुर जगमोहन सिह को उनकी रियासत से दूर बनारस में रखकर उनकी शिक्षा प्रारम्भ करवाई। उस समय का कायर और अत्याचारी अंग्रेज़ शासन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धाओं के परिवारों से भी इतना भयभीत था कि दूर बनारस में रखने के बावजूद भी ठाकुर जगमोहन सिह को बेहद कड़ी निगरानी में रखा जाता था। यहाँ तक कि उन्हें अपनी बहनों से राखी बँधवाने तक की इजाज़त नहीं थी। बनारस में भारतेन्दु हरिशचंद्र जी का सानिध्य मिलने से ठाकुर जगमोहन सिह भारतेन्दु जी के अभिन्न सखा बन गए। वह भारतीय हिन्दी साहित्य जगत के मूर्धन्य साहित्यकार बने तथा धमतरी रायपुर में तहसीलदार पद पर कार्य करते हुए अनेक ग्रंन्थों का सृजन किया।.इस मूर्धन्य साहित्यकार की रचनाये अर्थाभाव के कारण यत्र तत्र बिखर गयीं। आजादी के बाद विजय राघव गढ़ रियासत शासन की उपेक्षा के चलते खंडहर अवशेषों की नगरी बन गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर धमतरी में जगमोहन सिह की याद में विशाल भवन बनाकर लाइब्रेरी व म्युजियम बनाया हुआ है। परन्तु विडम्बना है कि अपनी जन्मभूमि में ही भुला दिए गए ठाकुर जगमोहन सिह। विजय राघव गढ़ का ऐतिहासिक किला भी पुरातत्व विभाग से हटाकर हैरिटेज होटल में तब्दील करने की राजनैतिक चालों के कारण देखरेख के अभाव में खंडहरों में तब्दील हो रहा है। वर्तमान मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विजय राघव गढ़ महोत्सव को दी जाने वालीं राशि भी बंद कर दी गयी है। स्वार्थपूर्ति की राजनीति के चलते शहीदों की स्मृतिया उपेक्षित होकर रह गयी हैं।

भारत के खिलाफ टी20 विश्वकप मैच खेलने पीसीबी ने रखीं शर्तें

लाहौर (एजेंसी)। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले आईसीसी टी20 विश्वकप मैच में खेलने को लेकर सौदेबाजी शुरु कर दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाक क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से कहा है कि वह भारत के खिलाफ विश्व कप में खेल सकता है पर उसकी तीन मांगों को पूरा करना होगा। पीसीबी को पता है कि आईसीसी इन मांगों को मानने तैयार नहीं होगा। उसकी मांग है कि बांग्लादेश को विश्वकप से बाहर किये जाने के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। बांग्लादेश को विश्वकप में भाग न लेने के बाद भी पार्टिसिपेशन फीस और 3- भविष्य के आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए पाकिस्तान को मेजबानी का अधिकार दिया जाए। इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने भी आईसीसी के सामने 2 मांगें रखी है। पहली मांग ये कि मुआवजा दो और दूसरी मांग ये कि आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी दो।

वहीं आईईसीसी के इस प्रकार की सौदेबाजी के लिए तैयार होने की संभावना नहीं है। इससे पहले पाक ने पिछले साल एशिया कप के दौरान भी टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी दी थी जब भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से मना कर दिया था। इस बाद उसने पूरा टूर्नोमेंट खेला था।

भांबरी-धाक्षिणेश्वर की मैराथन डबल्स जीत

नई दिल्ली। युकी भांबरी और धाक्षिणेश्वर सुरेश ने रविवार को खेले गए डेविस कप क्वालिफायर्स राउंड-1 मुकाबले में नीदरलैंड्स के खिलाफ रोमांचक डबल्स मैच जीतकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। भारतीय जोड़ी ने तीन घंटे तक चले मैराथन मुकाबले में डेविड पेल और सैंडर आरेंड्स को 7-6 (0), 3-6, 7-6 (1) से हराया। कप्तान रोहित राजपाल का एन. श्रीराम बालाजी की जगह धाक्षिणेश्वर को उतारने का फैसला निर्णायक साबित हुआ। 1-1 की बराबरी के बाद दोनों टीमें बढ़त हासिल करने के लिए बेताब थीं और यह मैच धैर्य, मानसिक मजबूती और दबाव में संयम की कड़ी परीक्षा बन गया।

पहला सेट

पहले सेट में भांबरी की सर्विस लगातार दबाव में रही, खासकर सातवें गेम में जब उनके पहले सर्विस ने साथ छोड़ दिया। 30-ऑल पर डबल फॉल्ट से डच जोड़ी को ब्रेक प्वाइंट मिला, लेकिन भांबरी ने सटीक रिटर्न से खतरा टाल दिया। इसके बाद धाक्षिणेश्वर ने गेम प्वाइंट पर आसान बैकहैंड वॉली चूक दी और आरेंड्स के अटपटे लेकिन असरदार ओवरहेड स्मैश से मेहमान टीम को फिर मौका मिला, मगर भारतीय जोड़ी ने किसी तरह गेम बचा लिया। 11वें गेम में भारत को पांच ब्रेक प्वाइंट झेलने पड़े, लेकिन भांबरी और धाक्षिणेश्वर ने सभी खतरे टालते हुए सर्विस बचाई, जिससे दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आखिरकार सेट टाईब्रेक में

दूसरा सेट

दूसरे सेट में मैच का रुख बदल गया। पेल की सर्विस पर भारतीय टीम मौके नहीं भुना सकी, जबकि भांबरी की डबल फॉल्ट से नीदरलैंड्स को अहम ब्रेक मिला। आरेंड्स ने शानदार बैकहैंड वॉली रिटर्न विनर लगाकर बढ़त बनाई और डच जोड़ी ने सेट जीतकर मुकाबला बराबर कर दिया।

तीसरा सेट

निर्णायक सेट में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। भारत को शुरुआती ब्रेक के कई मौके मिले, लेकिन वे उन्हें भुना नहीं सके। धाक्षिणेश्वर ने दबाव में शानदार खेल दिखाते हुए ब्रेक प्वाइंट बचाया। मैच का निर्णायक मोड़ तब आया जब आरेंड्स ने बाएं हाथ की चोट के कारण मेडिकल टाइमआउट लिया। इसके बाद उनकी सर्विस की धार कम हो गई, जिसका फायदा उठाकर भारतीय जोड़ी ने आखिरकार नियंत्रण हासिल किया और टाईब्रेक में मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने टाई में 2-1 की अहम बढ़त बना ली है। अब रिवर्स सिंगल्स में सुमित नागल का सामना जेस्पर डी यॉन्ग से होगा, जबकि इसके बाद धाक्षिणेश्वर सुरेश का मुकाबला गाय डेन ओडन से तय है।

लीवरपूल में प्रीमियर लीग

लीवरपूल में प्रीमियर लीग फुटबॉल में खेलते हुए लिवरपूल और मैनचेस्टर के खिलाड़ी।

पाक से मैच को लेकर आईसीसी के फैसले का सम्मान करेगा बीसीसीआईः राजीव शुक्ला

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि पाकिस्तान के टी20 विश्वकप मैच का बहिष्कार करने के मामले में बोर्ड अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के फैसले का सम्मान करेगा। शुक्ला ने कहा है कि इस मामले में आईसीसी के जो भी फैसला लेगी। उसी का हम पालन करेगी और हमारा कोई अलग रुख नहीं होगा। शुक्ला ने कहा, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि आईसीसी जो भी फैसला लेगा, बीसीसीआई उसी के अनुसार आगे बढ़ेगी। इस मामले में बोर्ड कुछ भी नहीं कहेगा। पाक ने बांग्लादेश को विश्वकप से बाहर किये जाने का विरोध करते हुए भारत के खिाफ विश्वकप मैच नहीं खेलने की बात कही है। वही पाक मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मैच की संभावनाएं हैं क्योंकि लाहौर में आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम के बीच इसको लेकर एक बैठक हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी इस मामले पर पाकिस्तान सरकार से स्पष्ट दिशा-निर्देश लेने वाला है। इसके बाद ही उसकी ओर से कोई औपचारिक घोषणा होगी। वहीं इससे पहले पाक सरकार ने कहा था कि उसकी टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस फैसले को बांग्लादेश से जुड़े विवाद से जोड़ते हुए कहा कि ये बांग्लादेश के प्रति समर्थन दिखाने के लिए लिया गया है। इससे पहले बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से अपने सभी मैच भारत से बाहर कराने की मांग की थी, जिसे आईसीसी ने ठुकरा दिया था। इसके बाद बांग्लादेश ने विश्वकप से नाम वापस ले लिया था। आईसीसी ने पीसीबी से यह स्पष्ट करने को कहा है कि उसने बहिष्कार का कदम क्यों उठाया है। वहीं पीसीबी ने आईसीसी को संदेश भेजा था कि सरकार के आदेशों के कारण वह इस मैच से बाहर रहेगा।

गंभीर के घर पर भारतीय टीम के लिए हुई डिनर पार्टी , बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी शामिल हुए

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को मुख्य कोच गौतम गंभीर के घर रात्रि भोज पर पहुंची। गंभीर ने टीम को अपने घर पर आमंत्रित किया था। इसमें खिलाड़ियों के साथ ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी शामिल हुए। गंभीर ने अपने परिवार के साथ भारतीय टीम का स्वागत किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने लजीज व्यंजनों का आनंद लिया। भारतीय टीम टी20 विश्वकप के 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ होने वाले मैच के लिए दिल्ली पहुंची थी। इससे पहले टीम ने मुम्बई में हुए पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ जीत हासिल की थी। भारतीय टीम के गंभीर के घर पहुंचने का एक वीडियों भी आया है। इसमें गंभीर और उनकी पत्नी टीम का स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। इससे लावा बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी गंभीर के घर पहुंचे। टीम का स्वागत करते हुए गंभीर और उनकी पत्नी नताशा व बच्चे बेहद खुश दिखे। इस पार्टी में कई प्रकार के व्यंजन और मीठे पकवान परोसे गए। इंडियन तंदूर के साथ ही चाइनीज और कांटिनेंटल इटालियन खाना भी परोसा गया। भारतीय खिलाड़ी बस से गौतम गंभीर के घर पहुंचे थे।

विश्वकप में भाग लेने नहीं मैच जीतने आयी है नेपाल टीमः पौडेल

मुम्बई (एजेंसी)। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाली नेपाल क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित पौडेल ने कहा है कि उनकी टीम विश्वकप में एक या दो टीमों को हराने का प्रयास करेगी। नेपाल का पहले टी20 मैच में अंतिम ओवर में केवल चार रनों से हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद से ही टीम के हौंसले बुलंद हैं। टीम दो बार के विश्व चैंपियन इंग्लैंड को हराने के करीब पहुंच गयी थी पर अंतिम ओवर में वह जीत के करीब आकर भी उसे हासिल नहीं कर पायी। पोडेल के अनुसार उनकी टीम का लक्ष्य हर मैच में जीत के इरादे से उतरना रहेगा। जिस प्रकार से टीम का पहले मैच में प्रदर्शन रहा है उससे उनकी टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है।

इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में नेपाल पर बड़ी मुश्किल से केवल 4 रनों से जीत हासिल की। इस मुकाबले में उलटफेर की संभावनाएं तेज थीं पर। गेंदबाज

सेम करन ने अंतिम ओवर में टीम को जीत दिला दी। इंग्लैंड के सात विकेट पर 184 रन के जवाब में नेपाल की टीम छह विकेट पर 180 रन ही बना पायी।

स्कॉटलैंड टी20 विश्वकप में

200 रन बनाने वाली पहली एसोसिएट टीम बनी

कोलकाता (एजेंसी)। बांग्लादेश के बाहर होने के बाद शामिल हुई स्कॉटलैंड की टीम ने टी20 विश्वकप क्रिकेट 2026 में एक नया रिकार्ड बना दिया। स्कॉटलैंड की टीम ने इटली के खिलाफ हुए मुकाबले में 207 रन बनाये और इसी के साथ ही वह 200 रन बनाने वाली पहली एसोसिएट टीम बन गयी है। इस मैच में इटली ने टॉस जीतकर स्कॉटलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। स्कॉटलैंड ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 207 रन बनाए। इसी के साथ ही स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप में

एसोसिएट टीम के तौर पर 200 या उससे अधिक रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिकी टीम के नाम था। पिछले टी20 विश्वकप में अमेरिका ने बतौर एसोसिएट टीम कनाडा के खिलाफ सबसे अधिक 197 रन बनाए थे।

टी 20 वर्ल्ड कप में इससे पहले साल 2024 में अमेरिका ने कनाडा के खिलाफ तीन विकेट पर 197 रन बनाये थे। /3 वहीं 2024 में कनाडा ने अमेरिका के खिलाफ पांच विकेट पर 194 रन बनाये थे। वहीं 2014 में नीदरलैंड ने आयरलैंड के खिलाफ 4 विकेट पर 193 रन बनाये थे।

मैच की बात करे तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड की टीम की शुरुआत सलामी बल्लेबाज जॉर्ज मुन्से और माइकल जोन्स ने की। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 13.5 ओवर में 126 रनों की साझेदारी हुई। जॉर्ज मुन्से ने 54 गेंदों पर 13 चौके और 2 छक्के लगाकर 84 रन बनाये। वहीं जोन्स ने 30 गेंदों पर 37 रन बनाए।

व्यापार

खेतों में किया काम, मैकेनिक बनकर पेट पाला, अब 4800 करोड़ के मालिक

बुर्ज खलीफा में 22 अमार्टमेंट, साधारण परिवार में जन्म

नई दिल्ली, एजेंसी। जॉर्ज वी नेरेमपरम्बिल भारतीय व्यवसायी हैं। उन्होंने बेशुमार दौलत और शोहरत कमाई है। वह मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। कभी मैकेनिक के तौर पर उन्होंने अपना और परिवार का पेट पाला। आज संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में नेरेमपरम्बिल सबसे सफल भारतीय मूल के व्यापारियों में से एक हैं। उनकी कुल संपत्ति 4,800 करोड़ रुपये बताई जाती है। उन्होंने दुबई की प्रतिष्ठित बुर्ज खलीफा में 22 लक्जरी अपार्टमेंट खरीदे हैं। यह उनकी असाधारण सफलता की कहानी को दिखाता है। आइए, यहां जॉर्ज वी नेरेमपरम्बिल के बारे में जानते हैं। जॉर्ज वी नेरेमपरम्बिल का जन्म केरल के एक साधारण परिवार में हुआ। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने परिवार का समर्थन करने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। नेरेमपरम्बिल ने अपने पिता के कृषि व्यापार में मदद की। खेतों के साथ एक मैकेनिक के रूप में भी काम किया। इन शुरुआती संघर्षों ने उन्हें अनुशासन और सफलता के लिए दृढ़ संकल्प का सबक सिखाया।

इस कंपनी की नींव डाली : जॉर्ज ने सीईओ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की, जो सालों से लगातार बढ़ी है। आज यह कंपनी खाड़ी के बुनियादी ढांचे और अनुबंध क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है। जॉर्ज इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं। यह जॉर्ज को पूरे क्षेत्र में बड़े

पैमाने की परियोजनाओं की देखरेख करने में मदद करता है। 2010 में एक रिश्तेदार की चुनौती पर जॉर्ज ने बुर्ज खलीफा में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। जो एक साहसिक कदम के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही एक प्रमुख निवेश रणनीति बन गया। कई वर्षों में उन्होंने प्रतिष्ठित टॉवर में 22 लक्जरी अपार्टमेंट खरीदे। इनमें से कई में सोने की थीम वाले इंटीरियर डिजाइन है।

कुमार मंगलम बिड़ला ने खरीदे वोडाफोन आइडिया के 4.09 करोड़ शेयर

नई दिल्ली, एजेंसी। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में सोमवार, 9 फरवरी को करीब 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ कारोबार शुरू हुआ। शेयरों में उछाल प्रमोटर कुमार मंगलम बिड़ला द्वारा पिछले सप्ताह कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने के बाद हुआ है। कुमार मंगलम बिड़ला ने 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच खुले बाजार से कुल 4.09 करोड़ शेयर खरीदे। इनमें से 2.21 करोड़ शेयर 30 जनवरी को औसतन 10.95 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे गए, जबकि 1.88 करोड़ शेयर 1 फरवरी को 11.13 रुपये प्रति शेयर पर खरीदे गए। यह खरीद कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 0.03 प्रतिशत है। सोमवार को सुबह 10 बजे के करीब वोडाफोन आइडिया के शेयर 2.97 पर्सेंट ऊपर 11.45 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। पिछले 5 दिनों में इसमें 5.25 पर्सेंट की तेजी दर्ज की गई है। जबकि, पिछले एक महीने में यह महज 1.78 पर्सेंट ही चढ़ा है। अगर पिछले छह महीने के प्रदर्शन की बात करें तो यह टेलीकॉम स्टॉक 73 पर्सेंट से अधिक का रिटर्न दिया है। हालांकि, इस साल अबतक इसमें 1.21 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। एक साल में यह शेयर 25 पर्सेंट से अधिक चढ़ा है। दिसंबर 2025 तक, केएम बिड़ला के पास वोडाफोन आइडिया में 0.02 प्रतिशत हिस्सेदारी यानी लगभग 1.94 करोड़ शेयर थे।

भारत में गोल्ड ईटीएफ में 98 प्रतिशत की उछाल

दुनिया भर में सोने में पैसा लगा रहे लोग

नई दिल्ली, एजेंसी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 में भारत के गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स में 2.49 अरब डॉलर का शुद्ध निवेश आया। यह दिसंबर 2025 के 1.25 अरब डॉलर के निवेश से 98 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी है। यह लगातार आठवां महीना है, जब इस क्षेत्र में निवेश बढ़ा है।

साल 2025 के मार्च और मई को छोड़कर हर महीने गोल्ड ईटीएफमें निवेश बढ़ा। पूरे 2025 में कुल 4.68 अरब डॉलर का निवेश आया, जो 2024 के 1.29 अरब डॉलर से 262 प्रतिशत अधिक है। इसकी तुलना में, 2023 में भारत के गोल्ड ईटीएफमें केवल 310 मिलियन डॉलर और 2022 में महज 33 मिलियन डॉलर ही निवेश आया

था। दुनियाभर में भी निवेशकों ने साल की शुरुआत में सोना ईटीएफ में पैसा लगाना जारी रखा। जनवरी में वैश्विक सोना ईटीएफमें 19 अरब डॉलर का निवेश आया, जो अब तक का सबसे मजबूत मंथली फंड फ्लो है। इस निवेश और सोने की कीमतों में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी ने वैश्विक सोना ञईटीएफ के प्रबंधन में जमा संपत्ति को रिकॉर्ड 669 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया, जो पिछले महीने की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि है। वैश्विक होल्डिंग भी 120 टन बढ़कर 4,145 टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। जनवरी में, फ्लो को शुरुआती कीमतों में तेजी और अमेरिका तथा ईरान, ग्रीनलैंड और यूरोप के कुछ हिस्सों जैसे क्षेत्रों के बीच बढ़े हुए भू-राजनीतिक तनावों ने समर्थन दिया। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने और आर्थिक गतिविधि का विस्तार होने का हवाला देने के बावजूद, केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को लेकर अनिश्चितता बनी रही। निवेशक इस बात पर केंद्रित रहे कि क्या नए फेड चेयर के रूप में नामित केविन वॉर्श राष्ट्रपति ट्रम्प की प्राथमिकताओं के साथ अधिक निकटता से जुड़ेंगे, जबकि चेयर पावेल को जारी जस्टिस विभाग की समन ने मौद्रिक नीति के भविष्य के रास्ते पर अनिश्चितता बढ़ा दी।

खुल गया एक और बड़ा आईपीओ, ग्रे मार्केट ने निवेशकों को डराया

जीएमपी 180 से टूटकर 13 पर आया

नई दिल्ली, एजेंसी। फैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ आज से ओपन हो गया है। कंपनी के आईपीओ का साइज 2833.90 करोड़ रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज संघर्ष कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में कंपनी के आईपीओ के जीएमपी में गिरावट आई है। कंपनी आईपीओ के जरिए 1.14 करोड़ फ्रेश शेयर और 2.01 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी। यह आईपीओ 9 फरवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 तक खुला रहेगा। फैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ का प्राइस बैंड 857 रुपये से 900 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 16 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14400 रुपये का दांव लगाना होगा। यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी। क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बीडर्स कैटगरी में कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा। वहीं, एनआईआई में अधिकतम 15 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 13 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 180 रुपये से घटकर 13 रुपये के स्तर पर आ गया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)